

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 23 अगस्त 2025 वर्ष-8,अंक-184 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com

 www.facebook.com/krantisamay1

 www.twitter.com/krantisamay1

योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा बुजुर्ग

-बीजेपी विधायक पर लगाए गंभीर आरोप



लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित जनता दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जहर खा लिया। गाजियाबाद के लोनी निवासी 65 वर्षीय सतवीर गुर्जर ने बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। घटना के तुरंत बाद सतवीर गुर्जर को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें 48 घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। गुर्जर ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब आठ बजकर 50 मिनट पर हुई। बयान में कहा गया है कि गुर्जर (65) नामक व्यक्ति 'जनता दरबार' में पहुंचा। गुर्जर ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि मैंने जहर खा लिया है। बयान के अनुसार, यह पता चलने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों व सुरक्षाकर्मियों ने बुजुर्ग को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल पहुंचाया।

पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टैस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। अग्नि-5 की रेंज 5000 किमी है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्किये जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्कर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दूरस्थों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी।

पीएम मोदी 25 अगस्त से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर, अहमदाबाद में 1449 आवासों करेंगे लोकार्पण

अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे पूर्वी अहमदाबाद के निकाल इलाके से 133.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1449 आवासों और 130 दुकानों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत कार्यान्वित इस परियोजना से झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक सुविधाओं युक्त उनका सपनों का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट घटक के तहत गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की स्लम रिडेविलिटेशन और रिडेवलपमेंट पॉलिसी-2013 के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के पश्चिम जोन के सरदार पटेल स्टेडियम वाई में स्थित रामापीपल टैकरा के नाम से पहचाने जाने वाले स्लम के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित कुल 1449 आवासों और 130 दुकानों के पुनर्वास कार्य का लोकार्पण होगा।

आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से मना कियास है। यह अर्जी एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) द्वारा आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और शेल्टर होम में रखने के लिए जारी किए नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। उन्होंने दलील दी कि एमसीडी का यह नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से पहले ही जारी किया गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच को अभी यह तय करना है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का दो जजों की बेंच का पुराना आदेश सही है या नहीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को अस्वीकार किया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महदेवन की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाकर शेल्टर होम में भेजा जाए और उन्हें वापस सड़कों पर न छोड़ा जाए।

भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है : शुभांशु शुक्ला

नई दिल्ली (एजेंसी)। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सओम-4 मिशन पर भारत सरकार, इसरो और अपने साथियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत आज भी अंतरिक्ष से सबसे अच्छा दिखता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने पिछले 10 सालों में हुई प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास हुआ है। साथ ही, उन्होंने नासा-इसरो के सहयोग और प्राइवेट कंपनियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बताया

कि वे फाल्कॉन 9 व्हीकल के ऊपर उड़ान भर रहे थे। उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार, इसरो और अपने सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ... हम फाल्कॉन 9 व्हीकल के ऊपर उड़ रहे थे... क्यू ड्रैगन उन तीन वाहनों में से एक है जो इसानों को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं... इस मिशन में मेरी भूमिका मिशन पायलट की थी। क्यू ड्रैगन में चार सीटें हैं। मैं मिशन पायलट था और मुखे कमांडर के साथ काम करना था और क्यू ड्रैगन के सिस्टम के साथ बातचीत करनी थी। हमें उन प्रयोगों को करना था जो भारतीय शोधकर्ताओं ने बताए थे। एसटीईएस प्रदर्शन, तस्वीरें और वीडियोग्राफ भी कैप्चर करने थे।'

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के चेयरमैन वी. नारायणन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद दक्षिण एशियाई देशों के लिए सैटेलाइट बनाई गई। उन्होंने कहा, '...पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का निर्माण, लॉन्च और दक्षिण एशियाई देशों को दान कर दिया गया। उनके नेतृत्व में, हमने जी20 देशों के लिए जी20 सैटेलाइट भी बनाया है... 10 साल पहले, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे पास केवल एक स्टार्टअप कंपनी थी। आज, अंतरिक्ष उद्योग में हमारे पास 300 से अधिक स्टार्टअप हैं...'

वी. नारायणन ने जीएसएलवी-

एफ16 रॉकेट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, '...जीएसएलवी-ख1 16 रॉकेट ने 30 जुलाई को सबसे प्रतिष्ठित नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को पूरी तरह से स्थापित किया। यह जेपीएल नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया एक सैटेलाइट है। आज, सैटेलाइट पूरी तरह से सही है। अगले 2-3 महीनों में, हम अमेरिका के 6500 किलोग्राम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, जिसे हमारे लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा।'

वी. नारायणन ने पिछले 10 सालों में हुई तरक्की के बारे में बताते हुए कहा, '...पिछले 10 वर्षों में, प्रगति अभूतपूर्व



और तेजी से हुई है। 2015 से 2025 तक पूरे किए गए मिशन 2005 से 2015 के लगभग दोगुने हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान, तीन महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए

हैं। अक्सियोम-4 मिशन एक प्रतिष्ठित मिशन है। पहले भारतीय को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाया गया और सुरक्षित रूप से वापस लाया गया।

संसद का मौनसून सत्र: विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का मौनसून सत्र 2025 गुरुवार को समाप्त हो गया। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और विपक्षी दलों के लगातार विरोध-प्रदर्शन के बीच लगभग हर दिन हंगामे का दौर देखने को मिला। अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध और हंगामे के चलते कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी और अंततः लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

संसद के मौनसून सत्र में विपक्षी संसद बिहार की मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) पर विस्तृत चर्चा की मांग करते रहे। विपक्ष ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर की साजिश का आरोप लगाया। सदन के भीतर



और बाहर इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की।

सदन की मर्यादा पर स्पीकर की ताजगी

संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन

अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का सुचारू संचालन आवश्यक है। लगातार जारी विरोध और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

ऑनलाइन गेमिंग बिल हुआ पास

इससे पहले हंगामे के बावजूद बुधवार को लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रचार और विनियमन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया। सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम विधेयक पेश किया, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। इस बिल का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और इसे राजनीतिक हथियार करार दिया।

सीएम रेखा को हमले के बाद मिली सीआरएफ वाली जेड कैटेगरी की सुरक्षा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए विशेष सुरक्षा प्रदान कर दी है। अब उन्हें सीआरपीएफ का जेड कैटेगरी सिक््योरिटी कवर दिया गया है। बुधवार रात से ही सीआरपीएफ कमांडो उनकी सुरक्षा



संभाल रहे हैं। यहां बताते चलें कि हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया (उम्र 41) को गुरुवार को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने उस पर हत्या की कोशिश सहित बीएनएस की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमले के बाद सीएम से मिलने नेताओं का तांता लग गया। मनोज तिवारी, बांसुरी खराज और सांसद योगेन्द्र चंदोलिया समेत कई नेता उनका हालचाल लेने पहुंचे। कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को आराम की जरूरत है और पुलिस को आरोपी के नेटवर्क की गहराई से जांच करनी चाहिए।

एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत सरकार ने कहा- मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं, द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने गुरुवार को कहा है- मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाइलैटरल सीरीज में इंडिया का स्टैंडबैरकर रहेगा।

खेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल इवेंट्स (चाहे भारत में हों या विदेश में) में भारत इंटरनेशनल खेल संस्थाओं के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। भारतीय टीमें और भारतीय खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। यह ठीक



वैसा ही है, जैसे भारत में होने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की

टीमें और खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे।

भरे मंच पर सीएम नीतीश ने मुस्लिम टोपी पहनने से किया इनकार, फिर जो हुआ...



तस्वीर खिंचवाने के बाद, बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान फिर से नीतीश को टोपी पहनाने के लिए मनाते हुए दिखाई देते हैं। हालाँकि, नीतीश मना कर देते हैं और टोपी खान के सिर पर रख देते हैं।

बिहार चुनाव की तैयारी में हैं?

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने

उपाधि मिली है। हाल ही में, जेडी(यू) की व्यावहारिक राजनीति ने मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को अल्प-थलग कर दिया है, खासकर तब जब पार्टी ने वक्फ कानून को अपना समर्थन दिया, जो मुसलमानों द्वारा दान की गई वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर सरकारी निगरानी का विस्तार करता है।

पांव मुस्लिम जेडीयू नेताओं ने पार्टी से किया किनारा

इस साल की शुरुआत में नीतीश द्वारा इस विधेयक का समर्थन करने के बाद कम से कम पांच मुस्लिम जेडी(यू) नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। यह विधेयक अप्रैल में संसद में पारित हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंशिक रूप से रोक लगा दी थी। जेडी(यू) की मुश्किलें नजर आते रहे हैं। हालाँकि, पिछले साल एनडीए में फिर से शामिल हुए नीतीश इस साल मार्च में अपने आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में प्याला पहने नजर नहीं आए। बार-बार पाला बदलने के कारण ही उन्हें 'पलटू चाचा' की

ई-वॉलेट्स से चंदा वसूली करने में जुटा जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर

3.9 अरब रुपये जुटाने की तैयारी में

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में बीते दो दशकों से ज्यादा समय से सीमा पार आतंकवाद फैलाने में जुटे जैश-ए-मोहम्मद ने अब फंडिंग जुटाने के नए तरीके खोज लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसके ठिकानों पर हमले किए थे। उसका मुख्यालय तब तबाह किया था। अब यह आतंकी संगठन फिर से सिर उठा रहा है और फाइनेंशियल एकशन टास्क फोर्स की नजर न पड़े, इसके लिए भी नए-नए पैंतरे अपना रहा है। इसी कड़ी में अब ई-वॉलेट्स से चंदा वसूली शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए ताकि पैमेंट्स को ट्रैक न किया जा सके। पाकिस्तान में प्रचलित ई-वॉलेट्स के के माध्यम से यह रकम अजहर के परिवार के लोगों के खते में जुटाए जा रहे हैं। यही नहीं ई-वॉलेट्स पर नए-नए अकाउंट बनाए जा रहे हैं ताकि किसी में भी एक साथ ज्यादा पैमेंट ना आए। इसी के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद का नया ढांचा खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी समूह एक समय में 7 से 8 ई-वॉलेट्स को सक्रिय रखता है। इसके बाद करीब 4 महीने में पुराने अकाउंट्स को बंद कर देता है और फिर हर महीने 30 नए खाते खोले जाते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर इस बार 3.9 अरब रुपये जुटाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं इस रकम से वह पूरे पाकिस्तान में 313 सेंटर बनाने की तैयारी में है।



अमेरिका, भारत- रूस और तेल व्यापार : इसे इस नजरिए से भी देखिए !

(लेखक--डॉ. मयंक चतुर्वेदी)

अमेरिका की नीति का एक और पहलू यह है कि वह भारत पर दबाव डालकर अपने तेल को बेचने का रास्ता साफ करना चाहता है। आंकड़े बताते हैं कि 2025 की पहली छमाही में भारत का अमेरिका से तेल आयात 51% बढ़कर 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया था, सबसे बड़ी बात यह है कि यह वृद्धि 2024 की पहली छमाही में 1.8 लाख बैरल प्रति दिन की तुलना में काफी अधिक है, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा है। यानी, अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी सूरत में रूस से तेल न खरीदे और मजबूरी में उससे खरीदे।

आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि हर देश की आर्थिक रीढ़ और सामरिक शक्ति का आधार है। तेल और गैस वैश्विक राजनीति के सबसे अहम औजार बन चुके हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसने रूस को रोकने के बजाय उसे नए बाजारों की ओर मोड़ दिया। भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देशों के लिए यह एक अवसर बनकर आया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। आज यही बात अमेरिका को खटक रही है।

अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25ब से बढ़ाकर 50ब तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, सिर्फ इसलिए कि भारत अपनी जनता और उद्योग को रूस से सस्ता तेल खरीदकर राहत दे रहा था। जबकि चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर अमेरिका ने अपेक्षाकृत नरमी बरती। यही नहीं, चीन के रिफाइनर रूस से पश्चिमी हिस्से का यूराल तेल खरीदकर और भी फायदा उठा रहे हैं। अगस्त 2025 के आँकड़ों के अनुसार, चीन ने लगभग 75,000 बैरल प्रतिदिन यूराल तेल खरीदा, जबकि उसका औसत पहले 40,000 बैरल था। दूसरी तरफ, भारत का आयात घटकर 4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि पहले यह 11.8 लाख बैरल प्रतिदिन था।

आज भारत के लिए रूस से तेल खरीदने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, कीमत। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो रूस ने तेल पर भारी छूट देनी शुरू की। 2022-23 में रूस भारत को 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक तेल बेच रहा था, और यह तेल मध्य पूर्व की तुलना में 20-30 डॉलर प्रति बैरल सस्ता था। दूसरा कारण है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की कुल ऊर्जा खपत का 85ब हिस्सा आयात से आता है। ऐसे में सस्ती स्प्लाइड पाना भारत के लिए सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता थी। अगर अमेरिका यह कहता है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्या अमेरिका की तेल कंपनियाँ केवल मानक सेवा के लिए काम करती हैं? क्या अमेरिका की शेल ओयल इंडस्ट्री सिर्फ घाटे में चलाने के लिए बनाई गई है? बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर देश और हर कंपनी मुनाफे के

लिए ही काम करती है, फिर भारत के मुनाफे पर अमेरिका की आपत्ति क्यों?

क्वाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की तेल खरीद को **"opportunistic and very bad"** कहा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत रूसी तेल खरीदकर सिर्फ अमीर भारतीय परिवारों को फायदा पहुँचा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने 16 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। लेकिन अगर यही तर्क मान लिया जाए, तो अमेरिका की शेल गैस कंपनियाँ, तेल निर्यातक, हथियार निर्माता और फार्मा कंपनियाँ भी तो मुनाफा ही कमा रही हैं। तो फिर भारत के मुनाफे पर इतनी तकलीफ क्यों? असलियत यह है कि अमेरिका दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर अकेले अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।

यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि भारत की रूस पर निर्भरता कोई स्थायी नहीं है, बल्कि व्यावहारिक है। भारत 2021 तक रूस से अपनी जरूरत का केवल 1ब से भी कम तेल खरीदता था। लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने डिस्काउंट देना शुरू किया और भारत ने इसका फायदा उठाया। इससे भारतीय जनता को महंगे पेट्रोल-डीजल से कुछ राहत मिली और रिफाइनरी कंपनियों को भी प्रतियुद्धी बढ़त मिली। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने दबाव बनाया और टैरिफ बढ़ाया, भारत की खरीद कम हो गई। परिणाम यह हुआ कि चीन ने यह अवसर तुरंत लपक लिया और रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। क्या अमेरिका को इस पर आपत्ति है? नहीं। क्यों? क्योंकि चीन से टकराने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है।

अमेरिका की नीति का एक और पहलू यह है कि वह भारत पर दबाव डालकर अपने तेल को बेचने का रास्ता साफ करना चाहता है। आंकड़े बताते हैं कि 2025 की पहली छमाही में भारत का अमेरिका से तेल आयात 51% बढ़कर 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया था, सबसे बड़ी बात यह है कि यह वृद्धि 2024 की पहली छमाही में 1.8 लाख बैरल प्रति दिन की तुलना में काफी अधिक है, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा है। यानी, अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी सूरत में रूस से तेल न खरीदे और मजबूरी में उससे खरीदे। यह एक प्रकार का आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत को सस्ते विकल्प छोड़कर महंगे विकल्प अपनाने के लिए मजबूर करना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।



भारत सरकार ने अमेरिका की इस नीति का विरोध भी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की तेल खरीद जरूरत के हिसाब से है, और पश्चिमी देश खुद भी रूस से कुछ व्यापार जारी रखे हुए हैं। यानी, जो काम अमेरिका और यूरोप खुद करें तो सही, लेकिन भारत करे तो गुनाह। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी जनता को सस्ता ऊर्जा स्रोत देने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। यही भारत का अधिकार है और यही किसी भी संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्रता का हिस्सा है। आज जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य निजी कंपनियाँ भी रूस से तेल खरीदकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद बेच रही हैं। इससे भारत को विदेशी मुद्रा आय हुई है। अगर चीन यही काम करे तो उसे 'व्यापारिक चतुराई' कहा जाता है, लेकिन भारत करे तो उसे 'खतरनाक' कहा जाता है। यह भेदभाव अब दुनिया की नजर से छिपा नहीं है।

वस्तुतः अमेरिका यह चाहता है कि ऊर्जा संसाधनों का उपयोग उसकी विदेश नीति के औजार के रूप में हो। रूस को

कमजोर करना, चीन को नियंत्रित करना और भारत को अपने खेमे में बनाए रखना, यह उसकी रणनीति है। लेकिन नया विश्व, जिसे हम **Global South** कहते हैं, अब इस दबाव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इन देशों की आवाज अब संयुक्त राष्ट्र और जी-20 जैसे मंचों पर गूँज रही है। तेल पर प्रतिबंध लगाना या टैरिफ के माध्यम से दबाव बनाना वास्तव में विकासशील देशों को पीछे धकेलना है। ऊर्जा के बिना विकास असंभव है। यदि भारत को सस्ता तेल रूस से मिलता है, तो इससे उद्योग को राहत मिलेगी, महंगाई नियंत्रित होगी और विकास तेज होगा।

अमेरिका का यह कहना कि भारत मुनाफा कमा रहा है, दरअसल उसकी अपनी खीझ का परिणाम कहा जा सकता है। अमेरिका को आज यह स्वीकार करना होगा कि हर देश अपने हित में काम करता है। भारत का रूस से तेल खरीदना न तो अनुचित है और न ही गैरकानूनी। यह पूरी तरह व्यावहारिक और आवश्यक कदम है। इसलिए अमेरिका को भारत की तेल खरीद पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

संपादकीय

मनी गेमिंग पर रोक

यह एक हकीकत है कि ऑन लाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति को भी बदहाल कर सकती है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर साल 45 करोड़ लोग बीस हजार करोड़ गवां देते हैं। सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते हैं। सवाल इन लालच जगाने वाली मनी गेमिंग की पारदर्शिता को लेकर भी उठते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं के बाद सरकार ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लेकर आई है। जिसे अब गंभीर चर्चा के बिना संसद ने पारित भी कर दिया है। यह विधेयक पैसे से खेले जाने वाले किसी भी ऑनलाइन गेम को गैरकानूनी घोषित करता है। दरअसल, सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सामाजिक और जन स्वास्थ्य के लिये घातक समस्या है। सरकार के मुताबिक, वह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक है, जिसमें कोई वित्तीय जोखिम न हो। निर्विवाद रूप से हाल के वर्षों में ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग ने तेजी से विस्तार किया है। जिसमें पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारों के प्रचार की भी भूमिका रही है। यहां उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग का वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही यह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। लेकिन इसके साथ चिंता का विषय यह भी है कि सुनहरे सज्जवाग दिखाने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप लत, खेलने वाले आम लोगों के आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले बदकिस्मत उपयोगकर्ता नाकामी के बाद आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। निस्संदेह सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा जोखिम भी उठाया है। इसमें सरकार को राजस्व की भारी हानि भी हो सकती है। वहीं तसवीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि कई उद्यमी तेजी से उभरते इस गेमिंग व्यवसाय के पराभव की चिंता जता रहे हैं। बताया जाता है कि देश में जो ग्यारह सौ से अधिक गेमिंग कंपनियां तथा करीब चार सौ स्टार्टअप ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं, जिनके नियमन के बारे में सोचा जा सकता था। उनकी चिंता है कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि उसने जनकल्याण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। लेकिन दूसरी ओर चिंता जतायी जा रही है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के वैध प्लेटफॉर्म बंद होने से खेलने वाले लोग अनियमित विदेशी ऑपरेटर्स के शिकार बन सकते हैं। इंटरनेट का विस्तृत दायरा और विदेशी ऑनलाइन ऑपरेटर विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। निस्संदेह, वित्तीय प्रणालियों की अखंडता के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस नये कानून को बनाने की जरूरत संभवतः छह हजार करोड़ रुपये वाले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के बाद महसूस की गई। जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों पर सट्टेबाजी एप के यूपई स्थित प्रमोटरों के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। जो कथित तौर पर हवाला कारोबार और विदेशों में धन-शोधन के कार्यों में लिप्त बताये जाते हैं। निस्संदेह, यह मामला सभी हिद्धारकों के लिये एक चेतावनी है, लेकिन इस बाबत कोई भी जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। इसके बजाय, ऑनलाइन मनी गेमिंग के सख्त नियमन और इसे भारी कराधान के अधीन लाना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता था।

विचारमंथन

(लेखक- सनत जैन)

- परिणाम से तय होगा देश का भविष्य

संसद का मानसून सत्र शुरू होने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हो गया। जिसके कारण रिक्त पद पर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। इस्तीफा देने के बाद से पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ अज्ञातवास में है। इस्तीफा के कारणों को लेकर भी तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। संसद के दोनों सदनों में पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद एसआईआर को लेकर दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। सरकार ने बिना चर्चा के एक दर्जन से ज्यादा बिल हंगामा के बीच पास कर दिये। ऑपरेशन सिंदूर में दोनों सदनों में लगभग 16-16 घंटे की चर्चा हुई। इसके अलावा संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह की तनातनी चल रही है। इस बीच सरकार ने एक नया बिल पेश किया। इस बिल को

जेपीसी के पास भेज दिया गया है। यदि यह बिल पास हो जाता है, तो केद्र में जो भी सरकार होगी। वह विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को या किसी भी प्रदेश की राजनीति को अपने ढंग से चलाने में सक्षम हो जाएगी। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं पर 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। कई नेता और अधिकारी जो नया बिल सरकार लेकर आ रही है उसके अनुसार 30 दिन की सी मुध्यमंत्री, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री हिरासत में रहता है। ऐसी स्थिति में उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ईडी का जो कानून है, उसके अनुसार न्यायालय से जमानत मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। ईडी के पास असंमित शक्तियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है। उन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिल पाई। कई राज्यों में ईडी के कारण विपक्षी दलों की सरकार गिर गई या राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इस बिल को सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों में इस बात का भय उत्पन्न हो गया है। यह बिल पास हो

जाएगा, उसके बाद देश में विपक्षी राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय दलों का कोई काम नहीं रह जाएगा। ऐसे विषम स्थिति पर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन को चुनाव मैदान में उतरा गया है। वह संघ एवं भाजपा से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए राजभवन से गिरफ्तार किया गया था। तब वह झारखंड के राज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ाकर राज्यसभा का सभापति बना दिया था। राज्यसभा में उन्होंने किस तरीके से काम किया है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के ही इशारे पर संसदीय कार्य करते हैं। उससे संसदीय परंपरा में विश्वास मरणान्न अवस्था में पहुंच गया है। वर्तमान स्थिति में मोदी सरकार गठबंधन की सहायता से चल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा 2024 और विधानसभाओं के चुनावों में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। इसको उजागर कर चुनाव

आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। सभी विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही थी। इसी बीच सरकार द्वारा जो बिल संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। उसमें 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री गिरफ्तार किया जाता है, 30 दिन हिरासत में रहता है। ऐसी स्थिति में उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसको लेकर रणनीति गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल भी सरकार के इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं संसय में आ गए हैं। सत्ता पक्ष ने तमिलनाडु के सीपी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन में फूट डालने और सत्ता पक्ष ने तमिल की राजनीति में एक दांव चला था। विपक्ष ने उसकी पहचाना, विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। उन्हें उम्मीदवार बनाकर सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यह और मात का जो खेल शुरू हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा, कहना मुश्किल

है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी प्रतियुद्धां दे रहे हैं। जिस तरह का संघर्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल रहा है वह रोमांचकारी है।

विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सीधी लड़ाई में जनता की अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता पक्ष अभी तक संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों के पीछे छिपकर जो खेल खेल रहा था, उसे विपक्ष ने समझ लिया है। विपक्ष जनता की अदालत में जाकर आर-पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर जो नियम और कानून बनाए थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक लोक सभा सीट के एक विधानसभा सीट में चुनाव आयोग द्वारा की गड़बड़ी उजागर किया है। संविधान और लोकतंत्र बचाने की एक लड़ाई बना दिया है। इस लड़ाई में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्षी एक जुटता ने सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है।

बदलाव के बीज से ही लहलहाएंगी फसलें

हमारे राजनेता और नीति-निर्माता क्यों नहीं चीन से यह बात सीखते कि कैसे उसने 12 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर एक ‘लाल रेखा’ खींच दी है, क्योंकि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते इतनी जमीन संरक्षित करना एक आवश्यकता है।

कुछ साल पहले, ‘इंडिया अग्रेस्ट करप्शन’ नामक संगठन के स्थापना-सर्ग के दौरान, अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि मैं उनके करीबी विश्वासपात्र मनीष सिसोदिया द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गुप्तनाम से गांव हिवारे बाजार पर बनाई गई एक दस्तावेजी फिल्म देखू, जो अपने चमत्कारिक कायाकल्प के कारण अचानक से खबरों में छाई थी।

सिसोदिया की इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक बारहों माह सूखाग्रस्त एवं अभावग्रस्त गांव ने ग्राम सभा में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अमल करते हुए, स्वशासन के जरिए खुद को एक जीवंत आदर्श गांव में बदल डाला। इस गांव में वयस्कों की औसत वार्षिक आय जहां वर्ष 1989 में महज 8,000 रुपये थी वह 2012-13 की शुरुआत में बढ़कर 28,000 रुपये हो गई। मुख्य रूप से, जनभागीदारी आधारित सर्वांगीण विकास के इस उल्लेखनीय मॉडल ने अंततः गांव में 54 करोड़पति पैदा कर दिए।

कोई हैरानी नहीं कि एक वक्त यह गांव सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाला रहा। जीडीपी से भी ज्यादा यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसने गरीबी और अभाव से जुड़े तमाम प्रतीकों जैसे कि बदती शराखोरी, बीमारियों का प्रसार, शिक्षा की कमी को सफलतापूर्वक रोक दिया। नतीजतन गांव में विपरीत-पलायन होने लगा। जब किसी गांव में आर्थिक बदलाव आता है, तो जो लोग पेट की खातिर गांव छोड़कर जाने को मजबूर हुए, वे वापस लौटना चाहते हैं।

कोई नौ साल पहले, मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब केजरीवाल ने ‘हिवारे बाजार की कहानी, अरविंद केजरीवाल की जुबानी’, नामक शीर्षक वाली अन्य यूट्यूब वीडियो की कहानी बड़ी वाक्पटुता से मुझे सुनाई थी। वह चाहते थे कि गांव के अद्भुत सरपंच पोपट लाल के नेतृत्व में जिस सामाजिक-आर्थिक सोच ने रास्ता दिखाया, उसका अनुसरण देश भर के सभी 7 लाख गांवों में किया जाए। बस उन्हें सुनिश्चित और आपको अहसास

होगा कि कैसे केजरीवाल ने ग्रामीण समृद्धि लाने की एक ‘पारसमणि’ खोज ली थी। दरअसल, वीडियो में वे एक नया पंजाब बनाने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इस कृषि प्रधान सूत्र में हिवारे बाजार की सफलता गाथा को लागू किया जाएगा। लेकिन, हमेशा की तरह, सरकार बनने के बाद, यह भी एक भूली-बिसरी कहानी बनकर रह गई।

पार्टी को मिले भारी चुनावी जनादेश को देखते हुए, यह अवसर निश्चित रूप से मौजूद था। कुल 117 सीटों में आम आदमी पार्टी को 92 पर मिली जीत के साथ, उसके पास हिवारे बाजार के अनूठे विकास मॉडल को अपनाकर भविष्य की राह फिर से गढ़ने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां थीं, जिससे आखिरकार एक नए पंजाब के उदय की रूपरेखा को प्रदर्शित किया जा सकता था। एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, बिखरती कृषि-आर्थिकी से स्थाई रूप से पार पाने के लिए जरूरी तमाम अवयव पंजाब के पास मौजूद हैं, न केवल जलवायु-अनुकूल है बल्कि आर्थिक-पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य और समृद्ध एक अद्भुत ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर भी। अगर एक सूखाग्रस्त गांव 54 करोड़पति पैदा करने पर गर्व कर सकता है, तो कल्पना कीजिए कि पंजाब के 12,000 से ज्यादा गांव, जहां पहले से ही 98 प्रतिशत खेत सिंचाई युक्त है, वहां कितनी बड़ी संख्या में करोड़पति आसानी से पैदा हो सकते हैं। अगर पानी को गांवों के विकास की धुरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो निश्चित रूप पंजाब से बहुत आगे है।

आवश्यक रूप से इसके लिए एक नई एवं कल्पनाशील सोच की आवश्यकता है, जिसका मास्टर प्लान पहले से ही मौजूद है। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ठंडे बस्ते में डालकर, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस महान अवसर को गंवा दिया है। और अब सिसोदिया द्वारा अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई यह नवीतम सलाह - ‘2027 का चुनाव जितवाने के लिए, साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा जो एक ऐसा पड़ेगा... तैयार हो जाओ के साथ?’ , सब कुछ उजागर कर जाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि लैंड पूलिंग योजना अकारण नहीं थी। मेरी हताशा राजनीतिक नेतृत्व की उस कथनी पर यकीन न कर पाने से भी है, जिसे वे बार-बार हमें बताते रहते

हैं। शुरुआत करने के लिए, निश्चित रूप से पंजाब को फसल विविधीकरण की जरूरत है, जो प्रचलित गेहूँ-धान फसल चक्र पद्धति की जगह ले सके, लेकिन लैंड पूलिंग वह विविधीकरण नहीं था जिसकी आज पंजाब को है। मेरी समझ में लैंड पूलिंग योजना वास्तव में नीति निर्माताओं में व्याप्त ‘बौद्धिक सुखे’ का अवस है और इसमें सेवारत के अलावा प्रभावशाली सेवानिवृत्त नौकरशाही, दोनों, शामिल हैं। कुछ महीने पहले पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित एक नीति संवाद में, सेवानिवृत्त नौकरशाहों को खेती की एजेंज में लेज ओद्योगीकरण की वकालत करते सुनना कोई हैरानी की बात नहीं थी।

यह सिर्फ पंजाब में सतारुद्ध आम आदमी पार्टी नहीं; देशभर में हर किस्म के राजनीतिक दल जमीनें हड़पने में लगे हैं। किसी भी प्रमुख दल का नाम लीजिए, उसकी नजर जमीन हड़पने पर ही है। हरियाणा आगामी 6 नए इंटिग्रेटेड मल्टीमॉडल टाउनशिप के लिए 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। कर्नाटक में, साढ़े तीन साल तक चले किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के आसपास के 13 गांवों तक फैले देवनहल्ली तालुका में 1,777 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने वाला फैसला वापस ले लिया है। इत्यादि।

इसे कुछ भी नाम दें, 164 गांवों में लगभग 65,553 एकड़ भूमि का अधिग्रहण उस तरह का विविधीकरण नहीं था जिसकी पंजाब को जरूरत थी। यह जमीन हड़पने की योजना के अलावा कुछ नहीं थी। हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चार हफ्तों के लिए लैंड पूलिंग नीति पर रोक लगाने के तुरंत बाद, किसान समूहों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसमें ट्रैक्टर रैलियां और कई गांवों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ‘प्रवेश निषेध’ नोटिस बोर्ड और बैनर लगाना शामिल थे, इसके चलते पंजाब सरकार द्वारा घातक नीति को वापस लेने का फैसला राहत की सांस के रूप में आया, जिसकी बहुत जरूरत थी। सन्द रहें, न्यायालय ने यह भी कहा था कि अधिगृहीत की जा रही भूमि अत्यंत उपजाऊं और द्विफसलीय है, जिसका अर्थ है कि केवल आसधारण मामलों में ही इसका अधिग्रहण हो सकता है, और इस तरह यह नीति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध जाती है।

लेखक कृषि एवं खाद्य संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं।

इच्छाओं को समर्पित करते जाओ

सभी इच्छाएं खुशी के लिए होती हैं। इच्छाओं का लक्ष्य ही यही है। किंतु इच्छा आपको कितनी बार लक्ष्य तक पहुंचाती है? इच्छा तुम्हें आनंद की ओर ले जाने का आभास देती है, वास्तव में वह ऐसा कर ही नहीं सकती। इसीलिए इसे माया कहते हैं। इच्छा कैसे पैदा होती है? किसी सुखद अनुभव की स्मृति या भूत के प्रभाव से इच्छा पैदा होती है। कुछ सुनने से भी इच्छा जागृत हो सकती है या किसी विशेष स्थान या व्यक्ति के संपर्क से। किसी और व्यक्ति की जरूरत या इच्छा भी तुम्हारी अपनी इच्छा के रूप में पैदा हो सकती है। मान लो कोई भूखा है, तो

तुम्हें उसे खिलाने की इच्छा हो सकती है, या कोई तुमसे बात करना चाहता हो तो तुम्हारी भी उससे बात करने की इच्छा हो सकती है। कभी-कभी नियति या कोई घटना जिसमें तुम्हें भाग लेना है, तुममें इच्छा जागृत करती है, पर तुम अपने कृत्यों का कारण नहीं जानते।

इच्छाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं, वे तुमसे पूछकर नहीं आती। जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तुम उनका क्या करते हो? यदि तुम सचते हो कि तुम इच्छाहीन हो जाओ, तो यह भी एक और इच्छा है। मैं एक उपाय बताता हूँ- सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती

है और यह टिकट प्रवेश द्वार पर देनी पड़ती है। यदि तुम उस टिकट को पकड़े रखोगे तो अंदर कैसे जाओगे? उसी प्रकार, यदि तुम किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहते हो तो आवेदन पत्र की जरूरत है। उसे भरकर जमा करना पड़ता है। उसे पकड़कर नहीं रख सकते। इसी प्रकार जीवन-यात्रा में भी अपनी इच्छाओं को पकड़कर मत रखो, उन्हें समर्पित करते जाओ। जैसे-जैसे समर्पण करते जाओगे, इच्छाएं भी कम उत्पन्न होंगी। सौभाग्यवान वे हैं जिनमें इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि इच्छा जागृत होने के पहले ही वे तृप्त हैं।

अब तक का सबसे रोचक उपराष्ट्रपति पद का चुनाव?

आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। सभी विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही थी। इसी बीच सरकार द्वारा जो बिल संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। उसमें 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री गिरफ्तार किया जाता है, 30 दिन हिरासत में रहता है। ऐसी स्थिति में उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसको लेकर रणनीति गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल भी सरकार के इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं संसय में आ गए हैं। सत्ता पक्ष ने तमिलनाडु के सीपी राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन में फूट डालने और सत्ता पक्ष ने तमिल की राजनीति में एक दांव चला था। विपक्ष ने उसकी पहचाना, विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। उन्हें उम्मीदवार बनाकर सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यह और मात का जो खेल शुरू हुआ है, उसका परिणाम क्या होगा, कहना मुश्किल



रेखा झुनझुनवाला ने गेमिंग के शेयर बेचकर करोड़ों कमाए

मुंबई । शेयर बाजार में जानकारी ही पैसा कमा सकते हैं। इस बात को सिद्ध किया रेखा झुनझुनवाला ने। उन्होंने कुछ महीने पहले ही ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनी के शेयर बेचकर भारी कमाई कर ली।मार्च 2025 तक रेखा झुनझुनवाला के पास 7.6 फ़ीसदी की हिस्सेदारी थी। उनके पास 61.8 लाख शेयर थे। 13 जून को उन्होंने अपने सारे शेयर 1225 रुपए प्रति शेयर में बेच दिए थे। जिससे उन्हें 334 करोड़ रुपए मिले। अन्य निवेशकों ने जिन्होंने अपने शेयरनहीं बेचे थे।उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाये गए बिल के बाद भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतिबंध के बाद 13 फ़ीसदी की गिरावट गेमिंग कंपनी नजारा टेक मे आई है। इसी कंपनी के शेयर रेखा झुनझुनवाला ने बेचे थे। यह शेयर उन्हें पति राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के बाद प्राप्त हुए थे। सही समय पर उन्होंने सही निर्णय लिया।

आईडीबीआई बैंक का जल्द होगा निजीकरण

नई दिल्ली । सरकारी बैंक आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार और एलआईसी की 95 फीसदी हिस्सेदारी में से लगभग 60.72 फीसदी शेयरों की बिक्री चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। वित्त विभाग के एक अे अधिकारी ने बताया कि इच्छुक निवेशकों को योग्य घोषित कर दिया गया है और वैल्यूएशन लगभग तय हो चुका है। इस कदम के तहत आईडीबीआई जल्द ही सरकारी नियंत्रण से बाहर आ जाएगा। अगर डील फाइनल होती है तो 2025 की शुरुआत में आईडीबीआई प्राइवेट बैंक बन जाएगा। इस खबर के बाद बैंक के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। सरकार जल्द ही अंतिम बोलीदाताओं के नाम सार्वजनिक कर सकती है, जिससे आगे की प्रक्रिया और स्पष्ट होगी।

स्नेहा ऑर्गेनिक्स का आईपीओ 29 अगस्त को खुलेगा

- मूल्य दायरा 115-122 रुपये प्रति शेयर



नई दिल्ली । हरित एवं टिकाऊ समाधान प्रदाता स्नेहा ऑर्गेनिक्स ने अपने आगामी आईपीओ के लिए प्रति शेयर 115 रुपये से 122 रुपये का मूल्य दायरा निर्धारित किया है। यह आईपीओ 29 अगस्त से अधिदान के लिए खुलेगा और 2 सितंबर को बंद होगा। कंपनी 27 लाख नए शेयर जारी कर कुल 32.68 करोड़ रुपये जुटाएगी। स्नेहा ऑर्गेनिक्स इस राशि का उपयोग अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। कंपनी का यह आईपीओ एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा, जो 5 सितंबर को संभव है। हरित समाधान क्षेत्र में कार्यरत इस कंपनी के इस कदम से निवेशकों को टिकाऊ और पर्यावरण-हितैषी कंपनियों में निवेश का अवसर मिलेगा। आगामी सूचीबद्धता से कंपनी की पूंजी वृद्धि और व्यवसाय विस्तार की संभावना बढ़ेगी।

वंदे भारत प्रोजेक्ट में जुपिटर वैनस को 215 करोड़ का बड़ा ऑर्डर

- कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना भी साझा की

मुंबई । रेलवे मोबिलिटी सॉल्यूशन कंपनी जुपिटर वैनस लिमिटेड को वंदे भारत ट्रेन परियोजना के तहत एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कंपनी की सब्सिडियरी जुपिटर त्रात्रावागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को 19 अगस्त को इस संबंध में लेटर आफ इंटेट मिला। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 5,376 आधुनिक व्हीलसेट (2,688 मोटर और 2,688 ट्रेलर) सप्लाई करने हैं, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 215 करोड़

संसद में पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक

- ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, मनी गेम्स पर लगेगी रोक

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देगा और समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखेगा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य है धन आधारित और सट्टा आधारित ऑनलाइन गेम्स पर रोक

लगाना और युवाओं के लिए एक सुरक्षित व रचनात्मक गेमिंग वातावरण तैयार करना। यह कानून समाज, विशेषकर युवाओं और संवेदनशील वर्गों को आर्थिक, मानसिक, और निजता से जुड़े खतरों से बचाने के उपाय करता है। विधेयक में लोक व्यवस्था, जनव्यवस्थ और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा यह अवैध सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइटों से चलने वाले मनी गेम्स पर सख्त नियंत्रण लगाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को एक सुनियोजित, पारदर्शी और जिम्मेदार फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया जाए। साथ ही ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर उन्हें नवाचार

भारत में पहला कार्यालय दिल्ली में खोलेगा ओपनएआई

तेजी से बढ़ते एआई बाजार को देखते हुए बड़ा कदम

नई दिल्ली । कृत्रिम मेधा (एआई) तकनीक में अग्रणी अमेरिकी कंपनी ओपनएआई ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह साल 2025 के अंत तक राजधानी दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोलने जा रही है। यह कदम भारत में उसके एआई उत्पादों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। भारत, अमेरिका के बाद चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता उपयोगकर्ता आधार बन चुका है। कंपनी ने बताया कि उसने भारत में आधिकारिक रूप से अपनी स्थानीय इकाई स्थापित कर दी है और एक समर्पित भारतीय टीम की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कार्यालय के जरिए ओपनएआई भारत सरकार, व्यवसायों, डेवलपर्स, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगी। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में एआई को लेकर जोश और संभावनाएं अविश्वसनीय हैं। यहां की तकनीकी प्रतिभा, विकसित डेवलपर समुदाय और सरकारी समर्थन इसे वैश्विक एआई नेता बनने की दिशा में अग्रसर करते हैं। यह निर्णय भारत में चैटजीपीटी गो, ओपनएआई एकडमी और इंडिक भाषा समर्थन जैसी पहलों की घोषणा के बाद आया है। इन पहलों का उद्देश्य भारत के उपयोगकर्ताओं को और अधिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करना है।

बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बड़े रोजगार के अवसर

- मिलेंगी 2.5 लाख नई नौकरियां

नई दिल्ली । एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इस वित्त वर्ष में 8.7 फीसदी और 2030 तक लगभग 10 फीसदी की दर से बढ़ेगा। इस वृद्धि से लगभग 2.5 लाख स्थायी नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। खास बात यह है कि हायरिंग केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी तेजी से भर्ती होगी।

2025 की पहली छमाही में इस सेक्टर में हायरिंग पिछले साल की तुलना में 27 फीसदी बढ़ी है। सबसे अधिक मांग फंटलाइन, डिजिटल और कम्प्लायंस से जुड़ी नौकरियों में देखी जा रही है। मिडिल और सीनियर लेवल पर ईएसजी स्ट्रेटेजी, डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट और एआईएफ या पीएमएस कम्प्लायंस जैसे नए क्षेत्रों में 30 फीसदी तक हायरिंग बढ़ी है। पब्लिक और प्राइवेट बैंक अपने कोर सिस्टम्स को मांडर्न

देश में दूध का उत्पादन पांच फीसदी बढ़ने की संभावना

वित्त वर्ष 24 में दूध उत्पादन 3.78 फीसदी बढ़कर 239.3 मिलियन टन तक पहुंचा

नई दिल्ली । भारत में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में दूध उत्पादन सालाना 5 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में भी दूध उत्पादन में 5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 24 में भारत का कुल दूध उत्पादन 3.78 फीसदी बढ़कर 239.3 मिलियन टन तक पहुंच गया। डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। खासकर छोटे और सीमांत किसान तथा महिलाएं इस क्षेत्र की मजबूत आधारशिला हैं। ये किसान डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। वित्त वर्ष 24 में दूध उत्पादन को कृषि उत्पादन का लगभग 19.8 फीसदी हिस्सा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता और खपत में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 20 से 24 के बीच प्रति व्यक्ति दूध की खपत में 3.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 24 में औसतन हर व्यक्ति के लिए

वेपार

रुपया गिरावट के साथ बंद हुआ

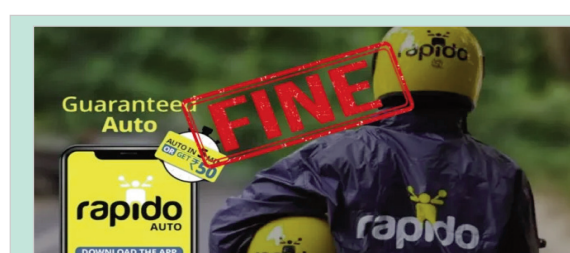
मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ 87.50 पर बंद हुआ। इसकी वजह डॉलर का मजबूत होना और एफआईआई की बिकवाली को माना जा रहा। मजबूत मांग के बीच शुक्रवार को भारतीय रुपया 11 पैसे टूटकर 87.36 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 87.37 पर खुला और जल्द ही 87.36 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद स्तर 87.25 से 11 पैसे की गिरावट दिखाता है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से रुपये पर दबाव बना है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सीमित विदेशी पूंजी प्रवाह के चलते रुपये में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। डॉलर सूचकांक, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाता है, 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ 98.72 पर पहुंच गया। इससे अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और स्पष्ट हो गई है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 693 , निफ्टी 213 अंक नीचे आया



फीसदी की कमजोरी के साथ 57,629.75 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 46.85 अंक तकरीबन 0.26 फीसदी की गिरावट के साथ 17,919.50 पर बंद हुआ। संसेक्स पैक में एमएंडइएम, मारुति सुजुकी, बीईएल, सन फार्मा, भारती एयरटेल और टाइटन के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे जबकि एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, एसबीआई, इटरनल, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर सबसे अधिक गिरे। इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुले। सुबह संसेक्स 81,951 अंक पर खुला और शुरुआती कारोबार में 227.24 अंक गिरकर 81,773.47 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने 25,064.15 पर शुरुआत की और



सीसीपीए ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

- धामक विज्ञापन का आरोप
नई दिल्ली । सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने 5 मिनट में ऑटो न मिलने पर 50 रुपए देने और गारंटीड ऑटो जैसे ध्रामक विज्ञापन दिए थे। जांच में पता चला कि 50 रुपए की जगह ग्राहकों को रैपिडो कॉइन दिए गए, जो केवल 7 दिन में खत्म हो जाते थे और बाइक राइड्स पर ही इस्तेमाल हो सकते थे। विज्ञापनों में डिस्कलेयर छोटे फॉन्ट में थे, जिससे उपभोक्ता उन्हें पढ़ नहीं सके। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ 1,200 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं। सीसीपीए ने कंपनी को आदेश दिया है कि जिन ग्राहकों को वादा के अनुसार मुआवजा नहीं मिला, उन्हें पैसे लौटाए जाएं।

आंध्र प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाएगी सरकार

- बंदरगाह विकास में 9,000 करोड़ का होगा निवेश



अमरावती । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश की 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा को देखते हुए सरकार ने हर 50 किलोमीटर पर एक बंदरगाह या हार्बर विकसित करने की रणनीति बनाई है। उन्होंने हाल ही में यह बात आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड और एक वैश्विक शिपिंग एवं पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी की सहायक इकाई के निवेश के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर समारोह में कही। इस समझौते के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपये के निवेश से रामयपट्टनम, मछलीपट्टनम और मुलुपेटा बंदरगाहों का विकास और आधुनिकीकरण किया जाएगा। कंपनी इन बंदरगाहों पर आधुनिक टर्मिनल और कार्गो हैंडलिंग सिस्टम स्थापित करेगी। इस पहल से लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का कहना है कि

जेआईसीए ने ग्लोबल सप्लाई चेन फंड में 4 करोड़ डॉलर का निवेश किया

- एशिया-अफ्रीका में व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

मुंबई । जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने शुक्रवार को आविष्कार कैपिटल के ग्लोबल सप्लाई चेन सेफोर्ट फंड में 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की। यह निवेश भारत, अफ्रीका और एशिया के उपरते बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करने और स्थानीय उद्यमों को सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया है। आविष्कार कैपिटल के अनुसार इस निवेश से जेआईसीए को भारत के साथ-साथ अफ्रीका और एशिया में भी विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की घोषणा जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने जापान के योकोहामा में आयोजित टीआईसीएडी-9 (अफ्रीकी विकास पर टोक्यो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन) के दौरान की। इस अवसर पर हिंद महासागर में आर्थिक भागीदारी - अफ्रीका

फोरम का आयोजन भी किया गया। जेआईसीए के एक वें रिष्ठ अे अधिकारी ने कहा कि यह निवेश भारत-जापान की मजबूत साझेदारी को और आगे बढ़ाएगा और अफ्रीका व एशिया में सतत विकास को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने इसे जेआईसीए और आविष्कार कैपिटल के बीच सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थायित्व और विविधता लाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है।

सरसों की फसल में लगाने वाले मुख्य कीट एवं उनका नियंत्रण

देश में रबी फसलों में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, सोयाबीन, मूंगफली के बाद सरसों की खेती देश भर में सबसे ज्यादा होती है। खाद्य तेल के रूप में सरसों की मांग अधिक रहने के कारण पिछले कुछ वर्षों से किसानों को सरसों की खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा है। सरसों का अच्छा उत्पादन कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे मिट्टी, जलवायु, बीज, रोग तथा कीट। कीट एवं रोगों का प्रभाव सीधे सरसों के उत्पादन पर होता है इसलिए किसानों को समय पर इनकी पहचान कर उन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है।

सरसों की फसल में समय-समय पर विभिन्न कीट एवं रोग काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज में कमी आती है। यदि समय रहते इन रोगों एवं कीटों का नियंत्रण कर लिया जाए तो सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। चेंपा या माहु, आरामकबी, चितकबरा कीट, मटर का पर्ण सुरंगक कीट आदि सरसों के मुख्य कीट हैं।

सरसों का माहू (चैपा /मोयला /एफिडा) कीट

सरसों का माहू छोटा, लंबा व कोमल शरीर वाला कीट है। प्रौढ़ माहू दो अवस्थाओं में पाया जाता है-पहला पंखरहित और दूसरा पंखसहित। पंखरहित प्रौढ़ 2 मि.मी. लंबे, गोलाकार व हरे रंग के या हल्के हरे पीले रंग के होते हैं। पंखसहित प्रौढ़ पीले उदर वाले व पंख पारदर्शी होते हैं। शिशु पंखरहित अवस्था के समान होते हैं, परन्तु आकार में छोटे होते हैं। दो नलीनुमा संरचनाएं (कोर्निकल्स) उदर के अंतिम भाग में उपस्थित होती है।

हानि के लक्षण

ये कीट प्रायः-दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में प्रकट होते हैं और मार्च के अंत तक सक्रिय रहते हैं और मार्च के अंत तक विभिन्न भागों जैसे - पुष्पक्रम, पत्ती, तना, टहनी व फलियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट समूहों में रहते हैं व तीव्रता से वंशवृद्धि करते हैं। माहू पहले फसल की वानस्पतिक कलिका पर प्रकट होते हैं व धीरे-धीरे पुरे पौधे को ढक लेते हैं। ये कीट मधुस्राव निकालते हैं और पौधों पर काले कवक का आक्रमण हो जाता है। तना व पत्तियां काली हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है। इस प्रकाश यह कीट उपज व तेल की मात्रा में कमी करता है। बादालयुक्त व ठंडा मौसम वंशवृद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है।

समन्वित कीट प्रबंधन

जहाँ तक संभव हो सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए, इससे फसल माहू के प्रकोप से बच जाती है। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए।

माहू के प्राथमिक आक्रमण पर 10 दिनों के अन्तराल पर 2-3 बार माहू ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर देने से माहू की वंशवृद्धि को कम किया जा सकता है।

फसल में कम से कम 10 प्रतिशत पौधे माहू से ग्रसित हों तथा प्रत्येक पौधे पर 26 से 28 माहू हों, तभी छिड़काव करना चाहिए।



ऑक्सी-डेमेटान मिथाइल (मेटासिस्टाक्स) 25 पायस सांद्रण अथवा डाइमिथोएट (रोगार) 30 पायस सांद्रण अथवा मैलाथियान 50 पायस सांद्रण की एक लीटर मात्र को 600-800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें

अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1708 एस.एल. को 5 मि.ली. / 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप हो तब 15 दिनों के अन्तराल से पुनः छिड़काव करें।

यह भी पढ़ें कृषि शांति योजना=मध्यप्रदेश

सरसों की आरा मक्खी

इस कीट की प्रौढ़ मक्खी 8-11 मि.मी. लंबी, पीले-नारंगी रंग की तटैया की तरह होती है। इसके पंख धूसर रंग के व काली शिरायें लिए हुए होते हैं। इसका अंडरोपक दांतेदार व आरिनुमा होता है इसलिए इसे आरा मक्खी कहते हैं। सर व टंगि काली होती है। इसकी सुड़ी गहरे हरे रंग की होती है, जिसकी पीठ पर पांच लंबवत धारियां होती है।

हानि के लक्षण

यह कीट मुख्य रूप से फसल की पौधावस्था (अक्टूबर-नवंबर) में ही नुकसान पहुंचाता है। सूड़ी, पत्तियों को काटकर उनमें अनियमित आकार के छेद कर देती हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे को कंकालित कर देती हैं। फसल में आक्रमण पौधावस्था में अधिक होता है और 3-4 सप्ताह पुरानी फसल में ज्यादा नुकसान होता है। मध्य जलवायु और कम आर्द्रता इसकी वंशवृद्धि के लिए अनुकूल है।

समन्वित कीट प्रबंधन

स्वच्छ कृषि क्रियाएं (खरपतवार नियंत्रण, वैकल्पिक पोषक पौधे व फसल अवशेषों आदि को नष्ट करना) अपनाना चाहिए।



गर्मियों के दिनों (मई-जून) में खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए।

फसल लगभग एक माह की हो जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। इससे इस कीट की सूड़ी पानी में डूबकर मर जाती है।

इस कीट के प्रकोप की अवस्था में मैलाथियान 50 पायस सांद्रण की एक लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

मटर का पर्ण सुरंगक कीट

प्रौढ़ मक्खी छोटी काले रंग की होती है और इसका सिर पिला होता है। प्रौढ़ मक्खी की लंबाई 1.5 मि.मी., पंख

विन्यास लगभग 4 मि.मी. व घरेलू मक्खी के समान परन्तु आकार में छोटी होती है। नए मोगटस कीट धूसर सफेद रंग के होते हैं और इनके मुखों काले भूरे रंग के होते हैं। पूर्ण विकसित कीट हरा पीला रंग का लगभग 3 मि.मी. चौड़ा, जिनका मध्य भाग मोटा और आगे से चपटा होता है। कीट पत्ती में सुरंग के अंदर रहता है और सुरंग में ही कृमिकोष में चला जाता है।

हानि के लक्षण

पौधे की पत्तियों में प्रौढ़ मादा के अन्डरोपक से अंडे देने के लिए छोटे-छोटे छेद करती है। प्रौढ़ मादा व नर इन छेदों से निकलने वाले रस को चूसते हैं। ये कीट पत्ती के पैरेनकाइमा ऊतकों को खाकर टेडी-मेडी सुरंग बनाते हैं। अत्यधिक ग्रसित पत्तियां पीली होकर गिर जाती है व उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिक प्रकोप की दशा में ग्रसित पत्तियां झिर जाती हैं। पौधों का ओज प्रभावित होता है और पुष्प एवं फलन गतिविधियां प्रभावित होती है। इस कीट का प्रकोप प्रायः-पुरानी पत्तियों पर अधिक होता है।

समन्वित कीट

ग्रसित पत्तियों को तोड़कर जमीन में दबा देना चाहिए, ताकि पत्तियों में छिपे



समन्वित कीट प्रबंधन

खेत में साफ़-सफाई रखनी चाहिए। खेतों के आसपास खरपतवार तथा फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए।

खेतों की गर्मियों के दिनों (मई-जून) में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए।

बुआई के 3-4 सप्ताह बाद यदि संभव हो, तो पहली सिंचाई कर देनी चाहिए।

पौधावस्था में इस कीट का आक्रमण होने पर क्यूनालफॉस 10 प्रतिशत अथवा मैलाथियान 5 प्रतिशत धुल की 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से धुकाव करें।

अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में मैलाथियान 50 पायस अथवा डाइमिथोएट (रोगार) 30 पायस सांद्रण की एक लीटर अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1708 एस.एल. की 150 मि.ली.मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

फसल का रंग सुनहरा होने पर ही कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की जल्द से जल्द मड़ाई कर लेनी चाहिए, जिसमें अधिक हानि न हो व पादप अवशेषों को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए।

कीट व कृमिकोष नष्ट हो जाएं।

ऑक्सी-डेमेटान मिथाइल 25 पायस सांद्रण या डाइमिथोएट 30 पायस सांद्रण की एक लीटर मात्रा को 600-800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें अथवा इमिडाक्लोप्रिड 1708 एस.एल. को 5 मि.ली. / 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें।

चितकबरा कीट

प्रौढ़ कीट के शरीर के ऊपर काले व चमकीले नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। प्रौढ़ 6.5-7.0 मि.मी. चौड़ा व पूर्ण विकसित शिशु 4 मि.मी. लंबा व 2.6 मि.मी. चौड़ा होता है। इन पर भूरी धारियां पाई जाती हैं। पहली व दूसरी अवस्था शिशु कीट का रंग चमकीला नारंगी और तीसरी व चौथी अवस्था का रंग लाल होता है। मुखों चूभाने-चूसने वाले एवं पंथीमुखी होते हैं।

हानि के लक्षण

ये कीट फसल के छोटे-छोटे पौधों को या पौध अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाते है। शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पौधे की पत्तियों एवं प्ररोह से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। फसल की दो पत्ती अवस्था में नुकसान होने पर ग्रसित उपरी भाग मुरझाकर सुख जाता है। वानस्पतिक अवस्था में प्रकोप के समय पत्तियों पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। पौधे का विगलन हो जाता है व पौधे पूर्णतः सुख जाते हैं। दोनों मामलों में फसल की दोबारा बुआई आवश्यक हो जाती है। यह कीट फली बनने व पकने की अवस्था में भी आक्रमण करता है, जिससे फलियाँ व दाने सिक्कुड जाते हैं। खलिहानों में कटी हुई फसल पर इन कीटों का आक्रमण व हानि को देखा जा सकता है। इस प्रकार यह कीट उपज व तेल की मात्रा में कमी करता है। मध्यम तापमान 20 से 40 डिग्री सेल्सियस व कम आर्द्रता इस कीट के गुणन के लिए उपयुक्त है।



कृषि क्षेत्र में किसान नई फसलों एवं नई किस्मों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में फसलों का चयन बाजार मांग के अनुसार करना चाहिए, जिससे किसानों को उचित भाव मिल सके। आज के समय में लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ बेबीकॉर्न की खपत में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वजह से इस फसल का बाजार मूल्य भी अधिक है एवं इससे बहुत से उत्पाद बनाए जाते हैं।

बेबीकॉर्न मक्का की ही एक प्रजाति है, लेकिन इसकी उपयोगिता के आधार पर बेबीकॉर्न नाम दिया गया है। बाजार में मांग के अनुसार किसानों के बीच खेती की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। पौधे का अनिर्बंधित भुट्टा होता और रेशमी बाल (सिल्क) निकलने के 2-3 दिनों के अंदर तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। यह काफी मुलायम होता है। समय बढने के साथ इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती जाती है।

बेबीकॉर्न से होने वाले लाभ

यह एक स्वादिष्ट व पौष्टिक आहार है, पत्तियों में लिपटा होने के कारण यह कीटनाशक दवाइयों के प्रभाव से मुक्त होता है। इस कारण यह स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। बेबीकॉर्न का उपयोग सलाद, सूप, सब्जी, अचार एवं कैडी, पकौड़ा, कोफ्ता, टिकी, बर्फी, लड्डू, हलवा, खीर इत्यादि के रूप में होता है। बेबीकॉर्न में फास्फोरस भरपूर मात्रा उपलब्ध होता है। इसके लिए अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्सियम, लौह व विटामिन भी उपलब्ध हैं। कोलेस्ट्रॉल रहित होने एवं रेशों की अधिकता के कारण यह एक निम्न कैलोरीयुक्त आहार है। यह हृदय रोगियों के लिए काफी लाभदायक है।

अधिक लाभ के लिए करें बेबीकॉर्न की खेती

मृदा का चयन एवं खेती की तैयारी

बेबीकॉर्न की खेती के लिए पर्याप्त जीवांशयुक्त दोमट मृदा अच्छी होती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा शेष जुताई देसी हल/रोटोवेटर या कल्टीवेटर द्वारा करके पाटा लगाकर खेत को तैयारी कर लेना चाहिए। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी के साथ-साथ खेत पलेवा करके तैयार करना चाहिए।

बुवाई समय एवं विधि

उत्तर भारत में बेबीकॉर्न फरवरी से नवंबर के मध्य कभी भी बोया जा सकता है। बुवाई मेडों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा मेड से मेड एवं पौधे से पौधे की दूरी 60 से.मी. म 15 से.मी. रखनी चाहिए। विभिन्न किस्मों के बीजों के आकार के अनुसार प्रति हैक्टेयर 22-25 किलोग्राम बीज दर उपयुक्त होती है।

उर्वरक प्रबंधन

अच्छी उपज के लिए उर्वरक का सही उपयोग होना चाहिए। फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट एवं 1/3 भाग नाईट्रोजन, बुआई के समय एवं 1/3 भाग बुआई के 25 दिनों बाद तथा शेष 1/3 भाग नाईट्रोजन 40 दिनों बाद डालना चाहिए। फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट एवं द भाग नाईट्रोजन बुआई के समय, द भाग नाईट्रोजन बुआई के 25 दिनों के बाद द भाग 60-80 दिनों के उपरांत तथा शेष नाईट्रोजन 80-110 दिनों के बाद देनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण

पहली निराई-गुड़ाई बुआई के 15-20 दिनों बाद तथा दूसरी



30 से 35 दिनों बाद अवश्य करनी चाहिए। इससे जड़ों में हवा का संचार होता है और ये दूर तक फैलकर भोज्य पदार्थ एकत्र करके पौधों को देती हैं। सीमाजीन 105 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर को 500-600 लीटर पानी में घोलकर बीज के अंकुरण के पूर्व खेत में छिड़काव करने से खरपतवार नहीं जमते और फसल तेजी से बढ़ती है।

बेबीकॉर्न की तुड़ाई का सही समय

मक्के की बेबीकॉर्न की गुल्ली को 3-4 से.मी. सिल्क (जीरा) आने पर तोड़ लेना चाहिए। गुल्ली तुड़ाई के समय ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए। पत्तियों को हटाने से ये जल्दी खराब हो जाती है। रबी में एक दो दिन छोड़कर गुल्ली की तुड़ाई करनी चाहिए। एकल क्रॉस संकर मक्का में 3- 4 तुड़ाई जरूरी है।

कितनी उपज प्राप्त होगी

इस तरह खेती करने से बेबीकॉर्न की छिलका रहित उपज 15-20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर प्राप्त होती है। इसके अलावा 200-250 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हरा चारा भी मिल जाता है। बेबीकॉर्न का छिलका तुड़ाई के दिन उतारकर प्लास्टिक की टोकरी, थैली या कंटेनर में रखकर तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए।

बेबी कॉर्न के साथ लगाएं अंतःफसल

रबी में बेबीकॉर्न के साथ आलू, मटर, राजमा, मेथी, धनिया, गोभी, शलजम, मूली, गाजर इत्यादि अंतःफसल के रूप में ली जाती है। अंतःफसल से जो उपज प्राप्त होती है वह अतिरिक्त लाभ होता है।



स्ट्राबेरी एक स्वादिष्ट, तुलाने वाला तथा पौष्टिक फल है। इसमें विटामिन सी तथा लोहा बहुतायत में होते हैं।

साधारणतः हिमाचल प्रदेश, उत्तर

प्रदेश तथा महाराष्ट्र में पैदा

किया जाता है।

किस्में : चान्दलर, गुरिल्ला,

टियोगा, सीस्के, स्वीटचाली,

डाना, टोरे, सेन्वा, बेल्सूपी,

फर्न, पंजारी इत्यादि।

नर्सरी तैयार करना - स्ट्राबेरी का

प्रवर्धन मुख्य रनर (पत्ता को पकड़ने

वाली नोक) द्वारा किया जाता है जाकि

कायिक प्रवर्धन का एक भाग है। एक पौधे से

7-10 रनर प्राप्त होते हैं। बड़े स्तर पर प्रवर्धन के लिए सूक्ष्म

प्रवर्धन (ऊतक प्रवर्धन) का प्रयोग करते हैं। इस विधि से पूरे

वर्ष पौधे प्राप्त करते हैं।

सस्य क्रियाएँ - भूमि को तैयार करना स्ट्रबेरी की खेती के लिए

जरूरी होता है। भूमि को जोतकर सममतल बनाते हैं। रनर का

रोपक समय सितम्बर -अक्टूबर है। रोपक करते समय

यह ध्यान रहे कि रनर स्वस्थ,, कीट एवं बीमारी रहित होने

चाहिए। चार तरीके से इसका रोपक करते हैं, जैसे - मैटिड से,

स्प्रेड से, हिल तथा प्लास्टिक फिल्म।

उर्वरण व खाद : भिन्न-भिन्न खद एवं उर्वरण की दर अलग-अलग

राज्यों के लिए निर्धारित की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए खाद व उर्वरण को इस प्रकार निर्धारित किया

गया है -50 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 40 कि.ग्रा.

फास्फोरस, 40 कि.ग्रा. पोटाश को भूमि तैयार करने समय डालते हैं। नत्रजन (80 कि.ग्रा.) को दो भागों में बांटका एक

भाग को सितम्बर और दूसरे भाग को फुल आते समय देना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण -खरपतवार नियंत्रण के लिए 3-4 निराई-गुड़ाई की आवश्यकता होती है। ड्यूरान रसायन 5

कि.ग्रा./हे. का एक छिड़काव फसल की गुड़ाई के बाद करें।

तुड़ाई एवं उपज -स्ट्राबेरी की तुड़ाई फलों के आधे से तीन

चौथाई भाग के रंग बदलने के पश्चात् करते हैं। फलों का पकना गर्म मौसम में शीघ्र होता है। फल की तुड़ाई डण्टल

सहित सुबह के समय करते हैं। इसकी उपज 90 क्विंटल/हे. आकी गई है। अच्छे उर्वरण प्रबंध द्वारा इसकी उपज 175-

200 क्विंटल/हे. तक होती है।

तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी

फलों की सतह का 2/3 हिस्सा लाल रंग का होने पर तुड़ाई करें।

छंटाई करके फलो को प्लास्टिक की पन्नेट (200 ग्राम) में पैक करें।

पन्नेट को सिंगल लेयर सीएफबी बाँधिये में रखें।

फलों को शीत गुह में 4-5 डिग्री से. तापमान व 85- 90

प्रतिशत आर्द्रता पर 20- 25 दिन के लिए भण्डारित करें।

फलों से जैम, जेली, आईसक्रीम आदि उत्पाद तैयार करें।

कीट प्रकोप एवं प्रबंधन

1. लाल मकड़ी माइट

ये लाल रंग के माइट पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं जिससे पत्तों पर धब्बे बन जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रूक जाने से उपज कम हो जाती है।

2. थिप्स

थिप्स पौधे के पत्तों व फलों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं।

इनसे फसल के बचाव के लिए एन्डोसल्फान 35

ई.सी. 2 मि.लि./लितर या कार्बेरिल 50 डब्ल्यू.पी. 2

ग्राम/लितर या डाइमिथेएट 30 ई.सी. 1 मि.लि./लितर का

छिड़काव करें।

3. पत्ती सूत्रकृमि (लीफ नेमाटोड)

यह सूत्रकृमि पौधे के नए फलों को नुसान पहुंचाता है जिससे ये टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं तथा इन पर स्लेटी रंग के धब्बे बन जाते हैं। पौधों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ने से ऊपर काफ़ी कम हो जाती है।

प्रबंधन

1. खेत की मिटटी का निर्जमीकरण करें।

2. रोपाई से पहले पौधे को 5 मिनट के लिए इसाजोफॉस 50 ई.सी. के 2 प्रतिशत घोल में डुबोएं।



महुआ मोइत्रा ने योगी पर तंज कसते हुए कहा... थोड़ी तो शर्म कीजिए

कोलकत्ता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार सुबह गाय की तस्वीरों के साथ कुछ ऐसा लिखा जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महुआ ने एक सरकारी गाय आश्रय केंद्र की तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में शेल्टर होम की गंदगी और बीमार गायें नजर आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि ये ग्रेटर नोएडा स्थित गाय शेल्टर होम का हाल है। गाय मुख्यमंत्री योगी को बहुत

प्रिय हैं। मोइत्रा ने यूपी के पशुपालन विभाग को टैग कर लिखा है थोड़ी तो शर्म कीजिए। बता दें कि महुआ पश्चिम बंगाल की कुष्माण्गर सीट से सांसद हैं। वह लोकसभा में अपने तेवर के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर कई मुद्दों पर मोदी सरकार की घेराबंदी करती दिखाती हैं।

आतंकी संबंधों के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों बर्खास्त

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संबंधों के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत की गई है। बर्खास्त किए गए दो कर्मचारियों में एक कुपवाड़ा के करनाहा का एक शिक्षक और दूसरा कुपवाड़ा के केरन का एक सहायक स्टॉकमैन था। जांच में यह साबित हुआ कि दोनों कर्मचारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए काम कर रहे थे। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक सबूत जुटाए थे। अगस्त 2020 में उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद से, सिन्हा आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों के साथ-साथ उनके मददगार नेटवर्क, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और सरकारी संस्थानों में मौजूद उनके समर्थकों के रूप में जाना जाता है, को भी निशाना बनाया है। 2020 से 2024 के बीच सुरक्षा बलों ने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) का उपयोग करते हुए, 70 से अधिक इस तरह के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किया गया है।

बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और उनके भाइयों के आवासों पर छापेमारी

बेंगलुरु (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गेमिंग एएम में कथित अवैध धन हस्तांतरण की जांच के तहत चित्रदुर्ग जिले के चक्रवर्ते कस्बे में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी और उनके भाइयों के आवासों पर छापेमारी की। ईडी अधिकारियों के अनुसार, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु और गोवा सहित 17 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। 20 वाहनों में सवार 40 से अधिक ईडी अधिकारियों ने केसी नागराज और केसी टिप्पेस्वामी के घरों सहित वीरेंद्र से जुड़ी कई संपत्तियों की तलाशी ली। यह कार्रवाई 2016 में वीरेंद्र के आवारा पर आयकर विभाग के छापे के वर्षों बाद हुई है, जिसमें एक बाथरूम में छिपाकर रखे गए 5 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 30 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। ईडी सूत्रों का आरोप है कि वीरेंद्र की कंपनियों रत्ना गोएड, रत्ना मट्टी सोर्स, पप्पी टेक्नोलॉजी और रत्ना गेमिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल गेमिंग एप से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण के लिए हुआ था। गौरतलब है कि 2016 में, विधायक वीरेंद्र, जो तब जेडी(एस) पार्टी में थे, को आयकर विभाग द्वारा उनके बाथरूम में एक गुप्त कक्ष में 5.70 करोड़ के नए नोट छिपाने के बाद गिरफ्तार किया था।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष ने मीडिया आउटलेट्स को भेजा नोटिस

हैदराबाद (एजेंसी)। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के अध्यक्ष और तेलुगु समाचार चैनल के प्रमुख, बोलिनेनी राजगोपाल नायडू ने दो मीडिया हाउस को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने उन पर 10 और 14 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हुई खबरों के माध्यम से अपनी और टीटीडी बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। नोटिस में नायडू ने आरोप लगाया है कि वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाले इन मीडिया आउटलेट्स ने दुर्भावनापूर्ण और झूठी रिपोर्टिंग की है। उनका दावा है कि यह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उनका मीडिया हाउस निष्पक्ष समाचार कवरेज देता है, जिससे दूसरे प्रबंधन कथित तौर पर खुश नहीं है। नायडू का कहना है कि रिपोर्टिंग से न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि दुनिया भर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्तों की भावनाओं को भी चोट पहुंची है। नायडू के वकील ने 18 अगस्त को साक्षी प्रबंधन को कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें निम्नलिखित मांगें की गई हैं कि टीवी और समाचार पत्र को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। और टीटीडी बोर्ड को 10 करोड़ का हर्जाना देना होगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो सीनियर अधिकारियों को आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के दो सीनियर अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होगा है। सतारुद एनडीए और विपक्ष दोनों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी गेधाकृष्णन, एनडीए के उम्मीदवार हैं जबकि इंडिया लोक ने जस्टिस (रवानिवृत्त) वी सुदर्शन रेड्डी अपना कैडिडेट बनाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शुरूकार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। स्वास्थ्य कारणां का हवाला देकर 21 जुलाई को मौनसूचन सत्र के पहले दिन जगदीश धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश मेनका गांधी... आक्रामक कुत्ते की परिभाषा तय होनी चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने पुराने आदेश को संशोधित कर कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, जिन कुत्तों में रेबीज के लक्षण हैं या जो आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस उसी जगह छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जिन कुत्तों में रेबीज के लक्षण हैं या जो आक्रामक हैं, उन्हें शेल्टर में अलग रखा जाएगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। इसके लिए नगर निगमों को हर वार्ड में फीडिंग ज़ोन बनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र



शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के सचिवों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। देशभर की हाई कोर्ट्स में आवारा कुत्तों से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और डॉग लवर्स ने स्वागत किया है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने फैसले पर खुशी

जताकर वैज्ञानिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने का कारण डर और विस्थापन होता है। उन्होंने जोर दिया कि आक्रामक कुत्ते की परिभाषा तय होनी चाहिए। मेनका गांधी ने फीडिंग ज़ोन बनाने के कोर्ट के फैसले की सराहना कर बताया कि इस काम के लिए सरकार ने 2,500 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील ननिता शर्मा ने फैसले को

सीएम रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में घुसा शख्स...विधायक के खिलाफ करने लगा नारेबाजी



नई दिल्ली (एजेंसी)। जनसुनवाई में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद फिर उनके कार्यक्रम में बड़ी घटना हुई है। शुक्रवार को गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान शख्स उनके कार्यक्रम में घुसा और खूब नारेबाजी की। घटना तब की है, जब गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंद सिंह लवली कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद थीं। तभी शख्स कार्यक्रम में घुसा और नारेबाजी करने लगा। हालांकि पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया है।

शख्स को पहचान अजीत नार निवासी प्रवीण शर्मा के तौर पर हुई है। वह 60 साल का है। उसका अजीत नार में टीवी केवल का बिजनेस भी है। शख्स ने दावा किया है कि वह बीते 40 सालों से बीजेपी का कार्यकर्ता है। जानकारी के मुताबिक विधायक लवली जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी प्रवीण शर्मा वहां पहुंचा और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगा।

शाहदरा के डीसीपी ने बताया कि आरोपी प्रवीण शर्मा बैरिकेड्स के पीछे और एक गली में हो था। यहां से शख्स को तुरंत पकड़ कर हटा दिया गया। किसी भी समय वोआईपी की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया गया।

बात दें कि सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। आरोपी राजेशभाई खिम्जनी ने बताया था कि उसने पहले आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भिष्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। यह योजना सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किए गए आंदोलन की तर्ज पर थी। उपरदिल्ली पुलिस को आरोपी राजेशभाई की पांच दिन की हिरासत मिल गई है जिससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घुबलाख कर रहे हैं। पुलिस उसके बयानों की पुष्टि कर रही है और बड़ी साजिश की संभावना की जांच कर रही है।

मुंबई को बारिश से राहत तो राजस्थान, बिहार-बंगाल और कई राज्यों में अब मूसलाधार का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा और इस कारण देशभर में मौसम का रुख भी बदल रहा है। मुंबई, जहां पिछले हफ्ते मूसलाधार बारिश ने चार साल का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया था, अब राहत की सांस लेता दिखा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश कराने वाला सिस्टम अब आगे बढ़कर गुजरात की ओर चला गया है। इस वजह से मुंबई में रविवार तक भारी बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि 24 अगस्त तक हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।

उधर, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आगे एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश ने कई हफ्तों से जारी सूखे को खत्म किया है। वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 26 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ल फटने का खतरा जाताया गया है।



गुजरात और पश्चिमी तट पर अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में गुजरात में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद 25 अगस्त से फिर से मूसलाधार बारिश का नया दौर शुरू होगा। कोकण, गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

उत्तर भारत की स्थिति

शैला। पटवारी ने कहा- 'ये लोग जनता को पेड़ लगाने के नाम पर वोट माँगते हैं और चुनावी सभा के लिए हजारों पेड़ काट डालते हैं। यही है भाजपा का 'ग्रीन इंडिया'। ये लोग मंदिर की घंटी बजाकर वोट लेते हैं और संसद की घंटी बजाकर लोकतंत्र बेच देते हैं।' विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा अब जनता के भरोसे को अपनी जेबखर्च की तरह इस्तेमाल कर रही है। किसानों से वादे करके उनके पसीने का दाम लूट लिया, युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा कर दिया, और अब जनता के वोट को अपनी प्राइवेट कंपनी का टोकन बना दिया। सहनी ने तंज कसते हुए कहा- 'भाजपा का असली काम

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को बिजली गिरने, भूस्खलन और जलभराव जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बौछारें जहां लोगों के लिए राहत बनीं वहीं भारी बारिश के साथ-साथ आफत भी लेकर आई हैं। बहरहाल अब मौसम बदल रहा है, इससे राहत मिलने की उम्मीद जागी है।

राजद सांसद संजय यादव ने भाजपा को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ठगी कंपनी है। उन्होंने कहा- 'चुनाव आयोग अब इनके लिए बैंक ऑफिस का काम करता है, और जनता के वोट इनके लिए मुफ्त की लूट है। भाजपा का नया नाम होना चाहिए- 'वोट चोर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड', जिसमें मालिक नरेंद्र मोदी, एजेंट अमित शाह और ठेकेदार उनके मुख्यमंत्री हैं।' उन्होंने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा- 'ये वही लोग हैं जो किसानों को एमएसपी से लूटते हैं, युवाओं को परीक्षा-पेपर लीक से धोखा देते हैं,

और चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखकर लोकतंत्र का तमाशा बनाते हैं।' कांग्रेस प्रवक्ता अनुपम कुमार ने भाजपा की राजनीति को एक बड़ा धोखा बताते हुए कहा- 'इनकी क्रोनोलॉजी बहुत साफ है- पहले विधायक चोरी, फिर वोट चोरी और अब पूरा राज्य सरकार चोरी।

भाजपा का नारा है 'जो बिकेगा वही टिकेगा'। वह पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें अपराधी घुसते ही संत बन जाते हैं, और ईमानदार आवाजें अंदर जाते ही देशद्रोही कहलाने लगती हैं।' अनुपम ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को 'डिस्कान्ट टेल' में बेच रही है, जहाँ विधायक बोली लगाकर खरीदे जाते हैं, मुख्यमंत्री गिफ्ट पैक में दिए जाते हैं और चुनाव आयोग बोनस में मिलता है।

शरद पवार के पोते रोहित को मिली जमानत, सहकारी बैंक घोटाले में हैं आरोपी

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को जमानत दे दी। विधायक रोहित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में आरोपी हैं जिसमें अदालत ने बड़ी राहत दी है। इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था। जानकारी अनुसार मुंबई की अदालत ने रोहित पवार को जमानत देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है, कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्री के खिलाफ आरोप पत्र तो दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान कभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश एसआर नवंदर ने कहा, कि इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले ही अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मूल अपराध ही बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस क्लोजर रिपोर्ट का ईडी ने विरोध किया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। दरअसल विशेष लोक अभियोजक सुनील गोसलवसे ने तर्क देते हुए कहा, कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए। कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज करते हुए कहा, कि ईडी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी तरह के खारिज किए गए मामले को चुनौती दे चुका है। इसी के साथ न्यायालय ने कहा, कि अपनी बात आप हाईकोर्ट के सामने रखें। बहरहाल कोर्ट 18 सितंबर से 10 अक्टूबर को क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू कर सकता है।

पिछला आदेश क्या था? बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि पकड़े गए किसी भी कुत्ते को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह फैसला जन-सुखा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, क्योंकि अधिकारी इस गंभीर समस्या से निपटने में असफल रहे थे। हालाँकि, अब इस आदेश में बदलाव कर दिया गया है।

पीएम किसान योजना की 12वीं से 20वीं किस्त तक की राशि एक साथ मिलेगी सरकार ने योजना को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने दस्तावेज दोबारा वरिफाई कर लेते हैं, तो 12वीं से 20वीं किस्त तक की राशि यानी कुल 18,000 रुपए एक साथ आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। ये खबर उन किसानों के लिए राहत है, जिनकी किस्तें किसी वजह से रुक गई थीं।

बता दें सरकार ने पीएम-किसान योजना को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इनमें आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड से लिंक करना और आधार से जुड़ा पेमेंट सिस्टम जैसे कदम शामिल हैं। अगर किसानों ने ये औपचारिकताएं समय पर पूरी नहीं कीं, तो उनकी किस्तें रोक दी गईं। पीएम किसान की 12वीं किस्त के लिए भूमि रिकॉर्ड से लिंक करना जरूरी था। वहीं, 13वीं किस्त के लिए आधार से पेमेंट सिस्टम लागू हुआ।



15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। इन नियमों की वजह से कुछ राज्यों में कई किसानों की किस्तें अटक गईं, खासकर जहां सत्यापन में देरी हुई।

अब अगर किसान इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो रुकी हुई सारी किस्तें एकमुश्त मिल जाएंगी। कृषि राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि जो किसान अब दस्तावेज पूर करे, उन्हें 12वीं से 20वीं किस्त तक की राशि यानी

18,000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान काम करने होंगे जैसे पीएम-किसान पोर्टल पर लॉगिन करें। फिर ई-केवाईसी पूरा करें। अपने आधार नंबर और बैंक खाते की लिंकिंग की पुष्टि करें। साथ ही, अपने राज्य के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करें और राशन कार्ड जैसे अन्य पहचान दस्तावेज वरिफाई कराएं।

सरकार ने ये बदलाव इसलिए किए हैं

ताकि योजना से जुड़ा फर्जीबाड़ी रुक जाए। इसके लिए पीएम-किसान पोर्टल को पल्लक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आधार डेटाबेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और राशन कार्ड डेटाबेस से जोड़ा गया है। इसका मकसद डुप्लीकेट खातों को हटाना, मृत लाभार्थियों के खातों को बंद करना और गलत लोगों को फायदा लेने से रोकना है, लेकिन इन बदलावों से कुछ किसानों को परेशानी हुई।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि सरकार का ये रवैया किसानों के साथ भेदभाव जैसा है। पहले ग्रामीण विकास फंड रोक दिया और अब किसानों की सीधी मदद भी अटक रही है। 20वीं किस्त की बात करें तो पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2025 को इसे जारी किया था। इस दौरान देशभर के लाखों किसानों के खातों में दो हजार रुपए की राशि भेजी गई।

यूट्यूबर एल्विश के घर पर गोलियां बरसाने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर

गुरुग्राम। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर का फरीदाबाद सेक्टर 30 के थाने की क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान इशांत उर्फ इशू के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। इशांत ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और बदमाश को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक इशांत ने इस दौरान पुलिस पर करीब आधा दर्जन फायरिंग की है। बता दें बीते रविवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। हालांकि एल्विश के परिवार के कुछ सदस्य घर में थे। लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। वहीं फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए तथा इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसाईं और फरार हो गए।

यूपी में हर व्यक्ति पर चढ़ा 37,500 रुपए का कर्ज

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी की योगी

आदित्यनाथ सरकार प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के टारगेट के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर काम किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच यूपी पर साल दर साल कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते यूपी का हर शख्स कर्ज में डूबा है, वो भी एक या दो हजार नहीं बल्कि 37,500 रुपए का ऋणी है।

यूपी पर पिछले पांच साल में छह लाख करोड़ से बढ़कर नौ लाख करोड़ रुपए उधार होने का अनुमान है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को राजस्व में 2.97 फीसदी घाटा हो रहा है। 2023-24 में राज्य सरकार पर कुल ऋण करीब 7.76 लाख करोड़ रुपये था जो वर्ष 2025-26 में 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने का अनुमान है। ऐसे में प्रदेश के हर व्यक्ति पर 37,500 रुपए का कर्ज है।

हालांकि, राज्य वित्त आयोग इसे राज्य के



विकास का संकेतक बता रहा है। राज्य वित्त आयोग का मानना है कि जितना राज्य की बुनियादी चीजों में खर्च होगा, उतना ही उधार बढ़ता है। इससे साफ है कि यूपी सरकार अपने आय से ज्यादा, यानी उधार लेकर पैसे खर्च कर रही है।

उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में राज्य पर बढ़ते ऋण पर नजर डाली जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 में ऋण 6,21,836 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2022-23 में 6,71,134 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023-24 में 7,76,783 करोड़, वित्त

वर्ष 2024-25 में 8,46,096 और 2025-26 ये बढ़कर 9,03,924 करोड़ रुपये हो गया। जानकारों को मुताबिक अगर किसी राज्य का ऋण ज्यादा होता है तो उसका सीधा दबाव विकासशील अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे ऋण पर लगने वाला ब्याज का ज्यादा भुगतान होता है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो राज्य के विकास के लिए इसका संतुलन बनाना जरूरी है।

वर्ष 2023-24 में 7,76,783 करोड़, वित्त

वर्ष 2023-24 में 7,76,783 करोड़, वित्त



सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता और राजेश रावैर (कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन, बिहार) भी उपस्थित रहे।

कारण जवाब दोगे। इस प्रेस वार्ता में अमर दुबे (एआईसीसी मीडिया प्रभारी, बिहार) और राजेश रावैर (कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन, बिहार) भी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

सीरिया में वरिष्ठ इस्लामिक स्टेट सदस्य अरेस्ट

दमिश्क, एजेंसी। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उत्तर-पश्चिम सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक वरिष्ठ सदस्य को गिरफ्तार किया है। बुधवार को चलाए गए इस अभियान की पुष्टि सीरियाई मीडिया और एक युद्ध निगरानी संगठन ने की। अधिकारियों ने पहचान का खुलासा नहीं किया है, ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पकड़ा गया शख्स आईएस का सर्वोच्च नेता है या कोई आम सदस्य। सूत्रों के अनुसार, इराकी नागरिक और आईएस कमांडर अबू हाफिज अल-कुरैशी को तुर्किये की सीमा के पास आतमह कस्बे में हेलीकॉप्टर से उतरे सैनिकों ने पकड़ा। ब्रिटेन की संस्था- सीरियन ऑब्जर्वेटरी फ़ॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, इस अभियान के दौरान एक अन्य इराकी नागरिक मारा गया। निगरानी समूह का दावा है कि गिरफ्तार शख्स के साथ फ्रेंच बोलने वाली एक महिला भी पकड़ी गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसे अमेरिकी बलों ने पकड़ा या बाद में सीरियाई सुरक्षा बलों ने। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम सलाह नोमान है। वह अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट में रह रहा था।

इसाइल में वेस्ट बैंक सेटलमेंट परियोजना को मंजूरी

येरुशलम, एजेंसी। इसाइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बस्ती बसाने की विवादस्पद परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। परियोजना लागू होने के बाद वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट सकता है। इस मामले में फलस्तीनी और मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में स्वतंत्र फलस्तीनी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। बुधवार को वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस मंजूरी को पश्चिमी देशों के को इसाइल का करारा जवाब बताया। स्मोट्रिच ने कहा, स्वतंत्र फलस्तीन अब नारेबाजी से नहीं बल्कि ठोस कदमों से मिटाया जा रहा है। हर बस्ती, हर मोहल्ला और हर मकान इस खतरनाक विचार के ताबूत में एक और कील है। इसाइल के इस निर्णय को क्षेत्र में तनाव बढ़ाने और शांति प्रक्रिया के लिए गंभीर झटका मारा जा रहा है। बता दें कि येरुशलम के पूर्व में ई। क्षेत्र में इसाइल बस्ती विकसित करने की योजना बना रहा है। बीते दो दशकों से इस पर विचार हो रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण अब तक इस पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

कांगो और एम23 विद्रोहियों के बीच शांति समझौते की कोशिश

किशासा, एजेंसी। कांगो सरकार और रवांडा समर्थित विद्रोही संगठन एम23 के बीच एक शांति समझौते का मसौदा तैयार हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य- उन इलाकों पर फिर से सरकारी नियंत्रण लाना है, जिन पर फिलहाल एम23 का कब्जा है। यह समझौता कतर की पहल पर तैयार किया गया है और इसमें शांति कायम करने के लिए तीन चरणों वाली प्रक्रिया का जिक्र है। आने वाले दिनों में दोनों पक्ष कतर की राजधानी दोहा में बैठकर इस मसौदे पर चर्चा करेंगे। कांगो के राष्ट्रपति फैलिवस त्लेसीकेदी अभी इस मसौदे से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं, बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने कहा कि राष्ट्रपति का मानना है कि मसौदा अभी अधूरा और असंतोषजनक है। वहीं, एम23 के नेता बर्टेंड बिसिमवा ने इस मसौदे पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान युद्धविराम लागू करने और कैदियों की रिहाई पर है, जो पहले से तय किए गए दोहा घोषणापत्र का हिस्सा है।

बोलीविया में चुनाव जाएगा नया राष्ट्रपति

सूट्ते, एजेंसी। बोलीविया में नया राष्ट्रपति चुनाव जाएगा। यह चुनाव देश में लगभग 20 साल से चल रही समाजवादी सरकार से बदलाव की ओर इशारा करता है। लेकिन आदिवासी समुदायों और पर्यावरण कार्यवाही को भरोसा नहीं है कि इससे अमेजन जंगलों की कटाई, आग या पट्टूण जैसी समस्याएं रुकेंगी। 19 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में दो नेता मध्यमार्गी रोलिगो पाज और दक्षिणपंथी जॉर्ज टूटो क्रिरोगा आमने-सामने हैं। दोनों बदलाव का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनका आर्थिक मॉडल बही है, जिसने अब तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। अमेजन जंगल नौ देशों में फैला हुआ है और यह दुनिया की जलवायु और कार्बन संतुलन के लिए बहुत अहम है।

ट्रंप के साथ बैठक के बाद वापस आते समय पुतिन को चुकाने पड़े 2.2 करोड़ रुपये

वाशिंगटन, एजेंसी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर

पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन से जंग को लेकर संघर्षविराम पर वार्ता के लिए अलास्का का दौरा किया था। यहां ट्रंप से वार्ता से पहले भले ही उनका रेड कॉप्टेड स्वगत हुआ हो लेकिन वहां से वापस आना पुतिन को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल, उन्हें वहां से वापस आते समय अपने विमानों में ईंधन भरवाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब इसके लिए उन्हें तकरीबन 250,000 डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) नकद चुकाने पड़े। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी हकीकत बताई है। उन्होंने साफ किया है कि पुतिन को ऐसा क्यों करना पड़ा। मार्को रूबियो ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका से लौटते समय तीन विमानों में ईंधन भरवाने के लिए लगभग 250,000 डॉलर (लगभग 2.2 करोड़ रुपये) नकद भुगतान करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यह रूस पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों का परिणाम था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जंग के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण वे हमारी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्हें ईंधन के लिए नकद भुगतान करना पड़ा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका द्वारा लागू गए प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और उनका प्रभाव भी बना हुआ है। रूबियो ने कहा कि रूस और पुतिन को हर दिन इसके परिणाम भुगताने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इन प्रतिबंधों ने युद्ध की दिशा नहीं बदली है।



बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा गौरतलब है कि 15 अगस्त को हुई बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए पुतिन की टीम अलास्का में लगभग पांच घंटे तक रही। ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें ट्रंप ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन से संघर्ष विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि दोनों के बीच वार्ता अच्छी रही। तीन साल से ज्यादा वक्त से रूस-यूक्रेन में जंग करीब तीन साल से ज्यादा समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध अब एक तरह के ठहराव पर है। रूस ने कुछ हिस्सों में हाल ही में बढ़त बनाई है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है।

अमेरिकी कोर्ट ने ट्रुफराई न्याय विभाग की मांग, गैड जूरी दस्तावेज सार्वजनिक करने से किया इनकार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के एक संघीय

न्यायाधीश ने जेफ्री एपस्टीन की मौत के मामले में बुधवार को ट्रंप प्रशासन को एक बार फिर झटका दिया है। इसके तहत न्यायाधीश ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़े देह व्यापार मामले की गैड जूरी की सुनवाई के दस्तावेज (ट्रांस्क्रिप्ट्स) सार्वजनिक करने की ट्रंप प्रशासन की मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले दो अन्य जज भी इसी तरह की मांग को ठुकरा चुके हैं।

मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रिचर्ड बर्मन ने कहा कि इन ट्रांस्क्रिप्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो जनता की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। साथ ही कहा कि असल में एपस्टीन से जुड़े करीब एक लाख पन्नों के दस्तावेज सरकार के पास हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जारी नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि सरकार के पास असली की ठोस जानकारी है, लेकिन वह सिर्फ ग्रैंड जूरी की सीमित जानकारी जारी करवाना चाहती है, जो कि असल तथ्यों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है।



ने पहली बार गाजा शहर पर कब्जा करने की मंजूरी दी थी, तब इजरायली अधिकारियों ने अनुमान जताया था कि इस योजना में पांच महीने या उससे ज्यादा का समय लग सकता है लेकिन बुधवार को नेतन्याहू ने सेना को समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है। बुधवार की शाम एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को आतंकवादियों के अंतिम गढ़ों पर कब्जा करने और हम्मास को हराने की समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है, जो गाजा शहर में आईडीएफ के आगामी हमले का संकेत है। नेतन्याहू ने दृष्टस से साफ कहा है कि

पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, ईशनिंदा के नाम पर सरेआम हो रही हत्या



लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। हिंदू और ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि पिछले साल हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह के मामलों में तेजी आई है। संगठन ने बताया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और नाबालिगों की शादियों की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट डर की गलियां: 2024-25

में धर्म या आस्था की स्वतंत्रता में देश में अहमदियों, हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बेहद चिंताजनक वर्ष का दस्तावेजीकरण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक वृद्धि हुई है, जिसमें अहमदिया समुदाय की लक्षित हत्याएं और उनके पूजा स्थलों का विध्वंस शामिल है।

एचआरसीपी ने बताया कि पंजाब और सिंध प्रांतों में हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह जारी है, जो बाल विवाह निरोधक कानूनों को लागू करने में व्यवस्थित विफलता को दर्शाता है।

संगठन ने कहा कि ईशनिंदा के आरोपियों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले बढ़े हैं। सबसे भयावह घटनाएं ईशनिंदा के आरोप में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की न्यायेतर हत्याएं हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने दो ईशनिंदा आरोपियों को उग्र भीड़ से सुरक्षा मांगने के दौरान न्यायेतर तरीके से मार डाला। यह घटनाएं कानून प्रवर्तन और जवाबदेही तंत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बार एसोसिएशनों का कट्टरपंथी धार्मिक समूहों की सोच की ओर झुकाव चिंताजनक है, जो विविध व्यवसाय की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निष्कर्षों के आधार पर ईशनिंदा के आरोपों में फंसाने की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की गई है। साथ ही, यह सुझाव दिया गया है कि अधिकारियों को उन मददसों पर नजर रखनी चाहिए जो अक्सर नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण में शामिल होते हैं।

भारत मूल्यवान साझेदार, मजबूत रिश्ते में खटास रणनीतिक आपदा: निक्की हेली

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में

अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत को चीन जैसा विरोधी नहीं, बल्कि एक मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार मानना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत के साथ पिछले 25 वर्षों से बने संबंधों की रफ्तार रोकता है, तो यह एक रणनीतिक आपदा होगी। निक्की हेली ने भारत और चीन के बीच एक मजबूत साझेदारी को बेहद आसान बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका उदय स्वतंत्र दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके उलट, चीन की ताकत बढ़ना दुनिया के लिए चुनौती है, क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन के तहत चलता है।

अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है भारत : निक्की हेली ने अपने लेख में कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है, जबकि चीन रूस से तेल खरीद कर प्रतिबंधों से बच रहा है और मार्को का सबसे बड़ा ग्राहक है। अमेरिका को



यह समझना होगा कि अगर एशिया में चीन का मुकाबला करना है तो भारत ही एकमात्र देश है जो यह संतुलन बना सकता है।

भारत में चीन की तरह बड़े पैमाने पर सामान बनाने की क्षमता : निक्की हेली ने आगे कहा कि भारत में इतनी क्षमता है कि वह तेल खरीद कर प्रतिबंधों से बच रहा है और चीन की तरह बड़े पैमाने पर सामान बना सकता है। इससे अमेरिका को अपनी सप्लाई

चेन चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। भारत कपड़े, सस्ते फोन और सोलर पैनल जैसे उत्पाद बड़े स्तर पर बना सकता है, जिन्हें अमेरिका खुद तुरंत या बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता।

मध्य पूर्व में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है भारत की भूमिका : हेली ने आगे कहा कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका उस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है, खासकर जब अमेरिका वहां सैनिकों और पैसों की संख्या कम करना चाहता है। भारत की भौगोलिक स्थिति चीन के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के रास्तों पर दबाव डाल सकती है, जो किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में चीन के विकल्प कम कर देगी।

आईडीएफ के विस्तारित सैन्य अभियान से शेष बंधकों की जान पर संकट बढ़ जाएगा। मानवाधिकार समूहों ने भी चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है। समूहों ने कहा कि गाजा में अधिकांश निवासी विस्थापित हो गए हैं, विशाल इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं और लोगों पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है।

इजरायली सैनिक अब हो रहे हताश : सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब दो साल से युद्ध लड़ रहे इजरायली सैनिक अब हताश होने लगे हैं। युद्ध का अंत नजदीक नहीं दिखने के कारण इजरायल के सैन्य प्रमुख ने सैनिकों पर बढ़ते बोझ की चेतावनी दी है, जिनमें से कई को गाजा में लड़ने के लिए कई बार बुलाया गया है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने इस महीने की शुरुआत में सुरक्षा कैबिनेट को बताया था कि सेना को क्षति और थकान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन सहयोगियों ने गाजा अभियान को आगे बढ़ाते हुए उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया।येरुशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय में अगम लेब्स के एक नए सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 40वें सैनिक युद्ध के लिए थोड़े या काफी कम प्रेरित थे, जबकि 13वें से थोड़े अधिक सैनिक युद्ध के लिए अधिक प्रेरित थे।

अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन, दयालु जज के नाम से फेमस हुए



सबसे दयालु जज कहते थे। उनका मानना था कि न्याय में दया और इंसानियत जरूर होनी चाहिए।

रोड आइलैंड में एक दिन के लिए झंडा आधा झुकाया : कैप्रियो का जन्म अमेरिका के रोड आइलैंड में हुआ था। रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने उन्हें राज्य का असली खजाना बताया। राज्य में उनके सम्मान में झंडे आधे झुका दिए गए हैं। उन्होंने लंबे समय तक म्यूनिसिपल जज के तौर पर काम किया। 2023 में उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें कैप्सर है। इलाज के दौरान वे लगातार लोगों से जुड़े रहे और अपडेट देते रहे। कैप्रियो पारिवारिक जीवन में भी बेहद समर्पित थे। परिवार ने कहा कि वे एक अच्छेपति, पिता, दादा और परदादा के रूप में याद किए जाएंगे।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था : निक्की हेली ने आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही जापान की पीछे छोड़ देगा। भारत का उदय चीन की उस महत्वाकांक्षा को रोक देगा, जिसमें वह वैश्विक व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की महत्वाकांक्षाएं घटेंगी।

अमेरिका-भारत की साझेदारी करने पर दोनों देशों के हित पूर्े होंगे : निक्की हेली ने यह भी याद दिलाया कि भारत और चीन के बीच कई विवाद हैं, जिनमें 2020 का गलवां घाटी संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और भारत साझेदारी करते हैं तो दोनों देशों के हित पूर्े होंगे और भारत चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकेगा। हेली ने चेतावनी दी कि अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद को अगर लंबा खींचा गया तो यह एक बड़ी और टाली न जा सकने वाली गलती होगी। चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

सूरत में असामाजिक तत्वों ने गणपति बप्पा के बैनर फाड़े

एक दिन पहले 15 प्रतिमाओं की उंगलियां तोड़ी गई थीं, पुलिस हरकत में आई

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर के वेसु इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति बप्पा के आगमन के बैनर फाड़े जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह घटना गुरुवार देर रात हुई मानी जा रही है।

डॉ. हेडगेवार नगर में गणपति बप्पा के आगमन पर लगाए गए स्वागत बैनरों को रात में 3 से 4 अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया। इससे पहले एक दिन पहले ही 15 गणेश प्रतिमाओं की उंगलियां तोड़ने की घटना हुई थी।

गणपति बप्पा के बैनर फाड़ने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ गणपति बैनरों को, बल्कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और कुछ स्थानीय दुकानों के बैनरों को



भी फाड़ा।

बैनर फाड़ते असामाजिक तत्व सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने वेसु पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार वेसु पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वेसु थाने के पीआई जे. आई. पटेल ने बताया कि

शिकायत मिलते ही तुरंत जांच शुरू की गई है और दो संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब गुरुवार को खटोदरा पुलिस थाने में गणेश मूर्ति वर्कशॉप में 10-15 गणेश प्रतिमाओं की उंगलियां तोड़े जाने की जांच पहले से चल रही थी।

सिविल अस्पताल के बिस्तर से रेप का आरोपी फरार

नई सिविल अस्पताल से बलात्कार और पोक्सो केस का आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत की नई सिविल अस्पताल से बलात्कार और पोक्सो केस का आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, जिससे पुलिस तंत्र में हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच, खटोदरा, चौकबाजार और वराछा पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं।

चौकबाजार पुलिस थाने में दर्ज पोक्सो केस में आरोपी को लाजपोर जेल से कोर्ट में पेश करने लाया गया था। इस दौरान अचानक आरोपी बेहोश होकर गिर पड़ा। तुरंत इलाज के लिए उसे सूरत सिविल अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही उसने मौके का फायदा उठाकर पुलिसकर्मियों की नजर से बचते हुए अस्पताल से फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया। फिलहाल, आरोपी की तलाश में क्राइम

फरारी में पुलिसकर्मियों की लापरवाही की भी जांच हो रही है।

खटोदरा थाने के पीआई बी.आर. रबारी ने बताया कि राजकोट जेल से चौकबाजार पुलिस स्टेशन के पोक्सो रेप आरोपी शुभम शर्मा को सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान उसे खींचते

सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक गिर पड़ा, अस्पताल ले जाते ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकला

समय वह गिर पड़ा था। जिसके बाद पुलिसकर्मी और इंचार्ज ने 108 एम्बुलेंस से उसे सूरत सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा।

इलाज के दौरान आरोपी ने अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में पुलिसकर्मियों की नजर से बचकर बिस्तर से उठते ही भागने में सफलता पाई। अब लोकल क्राइम ब्रांच, खटोदरा



ब्रांच, खटोदरा और वराछा पुलिस की टीमें सघन खोज अभियान चला रही हैं। आसपास के इलाकों और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी किस दिशा में भागा। साथ ही, आरोपी की

पुलिस और वराछा पुलिस की अलग-अलग टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। आरोपी चौकबाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज पोक्सो रेप केस का अभियुक्त है। चार महीने पहले उसकी जेल कस्टडी हुई थी और वह फिलहाल लाजपोर जेल में कच्चे काम का कैदी था।



हीरा घिसाई की मशीन में दुपट्टा फंसने से महिला के सिर के बाल खोपड़ी की त्वचा समेत उखड़ गए

सूरत में महिला रत्नकलाकार की हालत गंभीर, “सिर धड़ से अलग हो गया” के नाम पर वीडियो वायरल



लिए कतारगाम के एक छोटे कारखाने में रत्नकलाकार के रूप में काम करती थी। 20 अगस्त की सुबह वह काम पर

मैली विद्या के नाम पर ठगी

अंकलेश्वर में ‘भुवाई’ ने युवक के सोने के गहने और नकद 4.44 लाख हड़पे

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

अंकलेश्वर में मैली विद्या के नाम पर एक युवक से 4.44 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। नवा बोरभाठा के बलिया देव फलिया में रहने वाले सब्जी व्यापारी रोहन जयंती वसावा को पेट दर्द की

समस्या रहती थी।

रोहन अपनी मां, बहन और मौसी के साथ स्थानीय ‘भुवाई’ पुष्पा वसावा के पास गया। पुष्पा ने रोहन से कहा कि उसकी सोने की चेन पर किसी ने मैली विद्या कर दी है। विधि-विधान के बहाने उसने रोहन से सोने की चेन ले ली। सात दिन बाद चेन लौटाने का कहकर, अगले ही दिन उसने दूसरी सोने की चेन और अंगूठी

भी ले ली। इतना ही नहीं, पुष्पा ने रोहन से 20 हजार नकद लिए और बजाज फाइनेंस कार्ड से फर्नीचर भी खरीद लिया।

जब रोहन ने अपना सामान वापस मांगा तो भुवाई ने उसे झूठे केस में फँसाने की धमकी दी। इस पूरे मामले में रोहन ने अंकलेश्वर बी डिजिटल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

न्यूड वीडियो दिखाने के लालच में ठगी

पारडी के युवक से 1 लाख हड़पने वाली जम्मू की महिला गिरफ्तार

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

जम्मू के उधमपुर की 24 वर्षीय मंकाराधा अनिलकुमार भगतनी को पारडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला ने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन डालकर टेलीग्राम लिंक के जरिए न्यूड वीडियो दिखाने का लालच दिया था।

पारडी के एक युवक ने 10 मई 2025 को @monika-babyxx नाम की टेलीग्राम लिंक ओपन की थी। महिला ने विभिन्न पैकेज के नाम पर पैसे मांगे। युवक ने पहले 901 का पैकेज लिया था। उसके बाद सुरक्षा टैक्स, जीएसटी, टिप और रिफंड के बहाने और रकम की मांग की गई।

युवक ने SBI और एक्सिस बैंक से कुल 1,00,399 PI ID **miss.radha(@superyes** पर ट्रांसफर किए,



लेकिन न तो वीडियो मिला और न ही रिफंड। उल्टा और अधिक पैसे की मांग की गई।

इसके बाद युवक ने पारडी पुलिस से संपर्क किया। PI जी.आर. गढ़वी के नेतृत्व में पुलिस ने QR कोड, सोशल मीडिया ID, बैंक अकाउंट और

लोकेशन ट्रेस कर महिला को गिरफ्तार किया।

यह घटना दर्शाती है कि अज्ञात ऑनलाइन लिंक और लालच में आकर किए गए लेन-देन से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।

अहमदाबाद छात्रा हत्या केस

नवसारी में सिंधी समाज ने किया विरोध आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

कलेक्टर को सौंपा आवेदन

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

अहमदाबाद के खोखरा स्थित सेवन डे स्कूल में हुई छात्रा की हत्या के मामले में नवसारी में

सिंधी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। सिंधी युवा संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।

संगठन ने जिला उप कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। आवेदन में आरोपी को फांसी की सजा

देने की मांग की गई है। साथ ही, सेवन डे स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी उठाई गई। सिंधी समाज के लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।

SEIMER अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के बाहर रिक्शा पर ‘नो एंट्री’

गर्भवती महिलाओं समेत मरीजों को पैदल चलने की नौबत “सोच-समझकर निर्णय लिया”-अस्पताल के सुपरिटेडेंट

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत महानगरपालिका संचालित SEIMER अस्पताल में मरीजों के लिए कठिनाई भरा फैसला किया गया है। बड़ी संख्या में गरीब मरीज रिक्शा से अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अब उन्हें इमरजेंसी विभाग के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। इस कारण गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भी पैदल चलकर अंदर जाना पड़ रहा है।

सुपरिटेडेंट डॉक्टर जितेंद्र दर्शन ने कहा कि, चह्मने 10 दिन तक निरीक्षण करने के बाद सोच-समझकर यह निर्णय लिया है। हालांकि इस फैसले से मरीजों

और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

रिक्शा चालकों को इमरजेंसी गेट के बाहर ही रोक दिया जाता है। नतीजतन गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों के साथ आए परिजन और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को वहीं से पैदल जाना पड़ता है। पहले ही दिन से किसी भी रिक्शे को अंदर जाने नहीं दिया गया। पानी भरे इलाके में रिक्शा रोकने के कारण मरीजों और उनके परिवारजनों को पानी में उतरकर अंदर जाना पड़ा।

इमरजेंसी गेट पर रिक्शा रुकने से 108 एंबुलेंस को भी गुजरने में दिक्कत हो रही है। बाहर रिक्शों की भीड़ लग जाती है, जिससे अन्य वाहनों का ट्रैफिक

भी बाधित होता है। परबत गांव के 76 वर्षीय सोमनाथ चूलिलाल पांगोटारे, जिनका एक पैर कटा हुआ है, रिक्शा से इलाज कराने पहुंचे थे। उनकी रिक्शा को भी बाहर रोक दिया गया। थोड़ी बहस के बाद उन्हें इमरजेंसी तक जाने दिया गया और फिर व्हीलचेयर से दूसरे माले पर पहुंचाया गया।

सुपरिटेडेंट डॉक्टर जितेंद्र दर्शन ने कहा कि वीआईपी गेट पर रिक्शा चालकों को भीड़ रहती थी, जिसकी शिकायतें मिल रही थीं। इसलिए 10 दिन तक निरीक्षण के बाद यह कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए इमरजेंसी गेट पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है।

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कतारगाम इलाके में स्थित एक छोटे हीरे के कारखाने में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रत्नकलाकार महिला हीरा घिस रही थी, तभी उसके कंधे पर रखा दुपट्टा मशीन की पट्टी में फंस गया। दुपट्टे के साथ उसके बाल भी खिंच गए और सिर से सारे बाल खोपड़ी की त्वचा समेत अलग हो गए। महिला को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, चौकबाजार इलाके के उदयनगर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला परिवार की आर्थिक मदद के

पलों में उसके सिर से सारे बाल खोपड़ी की त्वचा समेत उखड़कर दूर जा गिरे। खोपड़ी से काफी खून बहने लगा।

तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, बाद में गंभीर हालत के चलते उसे लाल दरवाजा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के दो दिन बाद, तीसरे दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पड़ताल में सामने आया कि महिला जिंदा है और इलाज चल रहा है। साथ ही, कतारगाम पुलिस ने भी इस घटना की जानकारी दर्ज की है।

जैसे ही दुपट्टा मशीन में फंसा, महिला भी खिंच गई। सहकर्मियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही